घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 243- शनिवार 04- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से संभव

13 अगस्त तक 19 बैठकों की संभावना

- महिला आरक्षण,परिसीमन सहित कई अहम विधेयक हो सकते हैं पेश
- महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष

नई दिल्ली,03 जुलाई 2026। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने की संभावना है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार इस दौरान कुल 19 बैठकें आयोजित की जा सकती हैं। आगामी सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी-अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कई राजनीतिक दलों में हाल में हुए दलबदल और बदलते राजनीतिक समीकरण भी सदन की कार्यवाही को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की ओर से कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है। इनमें महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक प्रमुख हैं। दोनों ही संविधान संशोधन से जुड़े विधेयक हैं, जिन्हें पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होगा। महिला आरक्षण विधेयक पिछले सत्र में पारित नहीं हो सका था, इसलिए इसे दोबारा प्रस्तुत किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा सरकार संविधान (130वां संशोधन) विधेयक भी पेश कर सकती है, जो फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री 30 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहता है तो उसे पद छोड़ना होगा। इसके साथ ही एक देश-एक चुनाव, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफ सी आर ए) संशोधन, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने, कंपनी कानून में सुधार तथा शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई विधेयक भी सदन में लाए जा सकते हैं। दूसरी ओर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए व्यापक रणनीति बनाई है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें,राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक प्रकरण, राम मंदिर को मिले दान में कथित अनियमितताओं तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दलों में टूट-फूट और दलबदल के मामलों को भी विपक्ष सदन में उठाएगा। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों तथा शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के 6 सांसदों के दूसरे दलों में विलय से जुड़े मामलों पर निर्णय ले सकते हैं। साथ ही बागी सांसदों के सदन में बैठने की व्यवस्था को लेकर भी फैसला होने की संभावना है।

टीएमसी और शिवसेना के सांसदों पर होगा फैसला

सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला टीएमसी के बागी सांसदों और शिवसेना (यूबीटी) के कुछ सांसदों के नए गुट में शामिल होने से जुड़े मामलों पर फैसला ले सकते हैं। इन फैसलों का असर संसद के राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है।

सरकार पेश कर सकती है कई बड़े विधेयक

सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को फिर से ला सकती है। इसके अलावा 'एक देश, एक चुनाव' बिल, एफसीआरए संशोधन, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, एंटी-डोपिंग बिल और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़े विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं।

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला

स्कूलों के पास 500 मीटर के दायरे में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक

मुंबई,03 जुलाई 2026। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। यह घोषणा राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान की। सरकार का कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

कैफीन और चीनी को लेकर चिंता...

सरकार के अनुसार, स्टिंग जैसे एनर्जी ड्रिंक में कैफीन और चीनी की मात्रा अधिक होती है, जो बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने स्टिंग समेत छह एनर्जी ड्रिंक ब्रांडों को गलत ब्रांडिंग और भ्रामक दावों के मामले में नोटिस भी जारी किया है।

विधायकों ने उठाया था मुद्दा

भाजपा विधायक विक्रम पाचपुते ने विधानसभा में कहा कि स्टिंग की बोतल पर लिखा है कि यह छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है,फिर भी इसे बच्चों को बेचा जा रहा है। इसके बाद सरकार ने स्कूलों के आसपास इसकी बिक्री रोकने का फैसला लिया।

उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई...

सरकार ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी स्कूल के 500 मीटर के भीतर स्टिंग या अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूलों में बच्चों को एनर्जी ड्रिंक के नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जाएंगे।

15 साल बाद मिला न्याय...पुलिस कस्टडी में बेगुनाह की मौत पर थानेदार समेत 9 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद

वाशिम,03 जुलाई 2026। महाराष्ट्र के वाशिम से एक बेहद सनसनीखेज और न्याय व्यवस्था पर अटूट भरोसा जगाने वाली खबर सामने आई है। करीब 15 साल पहले एक बेगुनाह युवक को पुलिस कस्टडी में बेरहमी से पीट-पीटकर मार डालने के मामले में जिला अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। वाशिम जिला सत्र अदालत ने इस खौफनाक वारदात में शामिल तत्कालीन थानेदार समेत कुल 9 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सख्त सजा सुनाई है। इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं और भले ही न्याय मिलने में देरी हो,लेकिन दोषियों को उनके किए की सजा जरूर मिलती है। यह पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला 10 मई का है,जो करीब 15 साल पुराना है। रिसोड़ पुलिस ने रात के 3 बजे पारधी समाज से ताल्लुक रखने वाले बेग्या पवार नाम के एक युवक को उसके ही घर से उठाया था। उस वक्त परिजनों से सिर्फ इतना कहा गया था कि वे बेग्या को सामान्य पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन थाने ले जाने के बाद रक्षक ही भक्षक बन गए और पुलिसकर्मियों ने उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की कि कस्टडी में ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बाद में जब मृतक की मेडिकल जांच (पोस्टमार्टम) हुई, तो रिपोर्ट में उसके शरीर की कई हड्डियां टूटने की पुष्टि हुई थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि बेग्या पवार पर पहले से कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं था और घटना से महज एक साल पहले ही उसकी शादी हुई थी।

सेनाओं की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए 52 हजार करोड़ रुपये मंजूर,खरीदे जाएंगे हथियार

नई दिल्ली,03 जुलाई । केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए 52 हजार करोड़ रुपये से हथियार खरीदने को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में यह स्वीकृति मिलने से हथियार खरीदे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली 'आकाश तरंग' भारतीय सेना की युद्धक क्षमता बढ़ाएगी। सक्रिय सुरक्षा प्रणाली टैंकों की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने और काफी समय तक उनकी क्षमता को बढ़ाने में सक्षम होगी। इतिहास डीएसी की बैठक में रक्षा बलों के लिए लगभग 52 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर विभिन्न अधिग्रहण प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) यानी सैद्धांतिक प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। भारतीय सेना के लिए मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली 'आकाश तरंग', मानव-चालित टैंक-रोधी निर्देशित मिसाइल (एमपीएटीजीएम) प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल (एमआरएसएएम) हथियार प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली (वी-शोराड्स), टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकेज़ ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर आरएसएस का बड़ा बयान,पहली बार दत्तात्रेय होसबले बोले...दोषियों को मिले कठोर सजा...

संघ सरकार्यवाह बोले...करोड़ों रामभक्तों की आस्था को पहुंचा है आघात
ट्रस्ट और एसआईटी से पारदर्शी जांच व सख्त कार्रवाई की अपेक्षा

अयोध्या,03 जुलाई 2026। राम मंदिर के दान पात्रों से कथित धन चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यदि जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला करोड़ों रामभक्तों की आस्था और विश्वास से जुड़ा है,इसलिए इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच बेहद जरूरी है। होसबले ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष, त्याग और करोड़ों श्रद्धालुओं के समर्पण का प्रतीक है। ऐसे में दान पात्रों में जमा राशि से जुड़ी कथित गड़बड़ी की घटना ने पूरे हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आग्रह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है और अब कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। संघ की अपेक्षा है कि जांच पूरी निष्पक्षता से हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संघ सरकार्यवाह ने यह भी कहा कि इस घटना के बाद जो भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी है, उसे जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि मंदिर प्रबंधन और एसआईटी वित्तीय प्रबंधन,संचालन व्यवस्था और पारदर्शिता से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से समीक्षा करेंगे। उनका कहना था कि मजबूत और पारदर्शी व्यवस्थाएं ही श्रद्धालुओं के विश्वास को और सुदृढ़ बनाए रखेंगी। होसबले ने पूरे हिंदू समाज से भी धैर्य और संयम बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस घटना का फायदा उठाकर हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतें समाज और धार्मिक आस्था को बदनाम करने की कोशिश कर सकती हैं,इसलिए ऐसे प्रयासों को विफल करना सभी की जिम्मेदारी है। इस बीच, मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पिछले पांच वर्षों के खातों का दोबारा ऑडिट कराने का फैसला किया है। प्रारंभिक जांच में वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद अब निर्माण कार्यों पर हुए खर्च के साथ-साथ दान में मिले सोने-चांदी के आभूषणों और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का भी विस्तृत मिलान किया जाएगा। जांच एजेंसियों का उद्देश्य पूरे वित्तीय रिकॉर्ड की दोबारा समीक्षा कर किसी भी संभावित गड़बड़ी की पुष्टि करना है।

इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक विज्ञापनों को लेकर सरकार एक्शन में,मेटा को समन भेजने की तैयारी

नई दिल्ली,03 जुलाई 2026। केंद्र सरकार ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कथित आपत्तिजनक विज्ञापनों के मामले को गंभीरता से लिया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को मेटा से तुरंत जवाब मांगने के निर्देश दिए हैं। सरकार जानना चाहती है कि ऐसे विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंचे और उन्हें रोकने के लिए कंपनी ने क्या कदम उठाए।

मेटा से मांगा जाएगा स्पष्टीकरण...

सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय मेटा से उसकी विज्ञापन समीक्षा प्रक्रिया, कंटेंट मॉडरेशन और सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी मांगेगा। सरकार यह भी जांचना चाहती है कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए कंपनी क्या अतिरिक्त कदम उठाएगी।

व्हाट्सऐप फीचर पर भी सरकार की नजर...

इससे पहले केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप के प्रस्तावित यूजरनेम फीचर को लेकर भी मेटा को नोटिस भेजा था। सरकार ने कहा है कि इस फीचर को तब तक लॉन्च न किया जाए,जब तक इस पर पूरी चर्चा नहीं हो जाती। साथ ही कंपनी से तीन दिन के भीतर इस फीचर की विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है। सरकार का कहना है कि नए डिजिटल फीचर्स का दुरुपयोग साइबर अपराध,फर्जी पहचान,ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। इसके अलावा बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है।

'बम-बम भोले' के जयकारों के साथ अमरनाथ यात्रा शुरू,57 दिनों तक होंगे दर्शन,दूसरे जत्थे को भी मिली रवाना होने की अनुमति

पहलगाम/श्रीनगर,03 जुलाई 2026। बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन के लिए बहुप्रतीक्षित अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। अगले 57 दिनों तक ग्रेटर हिमालय की ऊंची वादियां 'बम-बम भोले' के जयकारों से गूंजती रहेंगी। 28 अगस्त तक श्रद्धालु समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से निर्मित हिम शिवलिंग के दर्शन कर सकेंगे। इस वर्ष यात्रा के दौरान चार लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। यात्रा के पहले दिन जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले जत्थे में 4,822 श्रद्धालु शामिल थे,जिन्हें 259 वाहनों के सुरक्षा काफिले के साथ बालटाल और पहलगाम मार्ग के लिए रवाना किया गया। लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं से दर्शन के बाद जल्द सुरक्षित स्थानों पर लौटने की अपील की है।

चलते ई-रिक्शा को बंद करने वाले चाइनीज ऐप बैन

नई दिल्ली,03 जुलाई 2026। देश की राजधानी दिल्ली में ई-रिक्शा को दूर से ही रोकने वाले दो चीनी मोबाइल ऐप्स पर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने इन दोनों ऐप्स को ऐप स्टोर से तुरंत हटाने का सख्त आदेश दे दिया है। इन खतरनाक ऐप्स के नाम बैट-बीएमएस हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही उन्हें इन दोनों ऐप्स की गड़बड़ी के बारे में पता चला, तुरंत कड़ा रुख अपनाते हुए इन्हें ब्लॉक कर दिया गया। सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने साफ कहा कि किसी भी ऐप स्टोर को अपने प्लेटफॉर्म पर ऐप्स को जगह देने से पहले पूरी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि देश की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।

साइबर सिक्योरिटी समिट में हुई बड़ी कार्रवाई की पुष्टि : इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से कार्रवाई की पुष्टि खुद सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने की है। उन्होंने एक बड़े साइबर सुरक्षा सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि यह खबर बिल्कुल सच है। सरकार को इन दोनों ऐप्स की संदिग्ध हरकतों के बारे में पता चला था,जिसके बाद कल ही इन दोनों ऐप्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित करके ऐप स्टोर से हटवा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस गंभीर विषय को ऐप स्टोर संचालकों के सामने भी उठाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी ऐप डाउनलोड के लिए उपलब्ध न रहे।

थलापति विजय ने कर दिया खेला...ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम में लगाई बड़ी सेंध,तीन पूर्व मंत्री समर्थकों समेत टीवीके में शामिल

चेन्नई,03 जुलाई 2026। तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री और मशहूर अभिनेता थलापति विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कषगम' का ग्राफ राज्य में तेजी से ऊपर जा रहा है। मुख्यमंत्री विजय ने विपक्षी खेमे में बड़ी सेंधमारी करते हुए ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम को गहरा झटका दिया है। मामल्लापुरम में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम के तीन दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ टीवीके में शामिल हो गए। वहीं, इस पूरे घटनाक्रम पर डीएमके ने चुटकी लेते हुए 'वॉशिंग मशीन' का तंज कसा है।

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम के इन दिग्गजों ने थामा टीवीके का दामन : टीवीके के महासचिव एन. आनंद की मौजूदगी मेंऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम के जिन तीन बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है,उनमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ.सी. विजयभास्कर,पूर्व परिवहन मंत्री एम.आर. विजय भास्कर और 45 सालों तक ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम से जुड़े रहे एम.एस.एम. आनंदन शामिल हैं। टीवीके में शामिल होने से पहले सी. विजयभास्कर ने विरालीमलाई सीट से और एम. आर. विजय भास्कर ने करूर सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं ने मुख्यमंत्री विजय के कामकाज और विजन की जमकर तारीफ की। पूर्व मंत्री आनंदन ने कहा कि उन्हें तमिलनाडु का राजनीतिक भविष्य अब टीवीके में ही नजर आता है। उन्होंने किसी भी तरह की 'खरीद-फरोख्त' के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम नेतृत्व पर साधा निशाना, बताया 'कॉरपोरेट कंपनी' : टीवीके में शामिल हुए नेताओं ने अपनी पुरानी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम के मौजूदा नेतृत्व और पार्टी महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी पर तीखे हमले किए। टीवीके के मुख्य समन्वयक के. ए. सेंगोट्टैयन ने कहा कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम अब एक राजनीतिक संगठन न रहकर 'कॉरपोरेट कंपनी' की तरह काम कर रही है। उन्होंने पलानीस्वामी को 'विश्वासघात' का प्रतीक बताया और आरोप लगाया कि उन्होंने डीएमके जैसी घोर विरोधी पार्टी से तालमेल बिठाने की कोशिश कर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया है। नेताओं का कहना था कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम नेतृत्व के 'गलत फैसलों' से निराश होकर ही उन्होंने यह कदम उठाया है। इस सियासी उथल-पुथल पर सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

द्रविड़ मुनेत्र कषगम की उपमहासचिव कनिमोई ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा,'सुना है उत्तर भारत में बीजेपी जो 'वॉशिंग मशीन' इस्तेमाल करती थी,वह अब तमिलनाडु भी पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि यह नई मशीन गुटखा के दाग भी साफ कर सकती है।' उनका यह तंज डॉ. सी.विजय भास्कर की 'गुटखा घोटाले' में कथित संलिप्तता को लेकर था।

वैवाहिक विवाद एक-दूसरे को नीचा दिखाने या बदला लेने की प्रतियोगिता नहीं,हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

नई दिल्ली,03 जुलाई 2026। वैवाहिक विवाद पति-पत्नी के बीच आपसी मतभेद हैं, न कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतियोगिता. दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक मुकदमों यानी तलाक और पारिवारिक विवाद के एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान ये गंभीर टिप्पणी की। जस्टिस सचिन दत्ता ने स्पष्ट किया है कि वैवाहिक विवाद एक-दूसरे को नीचा दिखाने या बदला लेने की प्रतियोगिता नहीं हैं। क्योंकि इस मामले में एक पक्ष ने दूसरे की अंतरंग तस्वीरें भी अपने दावे मजबूत करने के लिए अदालत के दस्तावेजों में लगा दी थी। दरअसल इस मामले में पति ने अपनी अलग रह रही पत्नी की निजी यानी अंतरंग तस्वीरें वैवाहिक अदालत में दाखिल कर दी थी। इसे गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने इसे गंभीर चूक बताया है। अदालत ने मुकदमे के पक्षकारों और वकीलों को भी ऐसी अविवेकपूर्ण हरकतों से बचने की ताकीद की। हालांकि पत्नी की ओर से पति और उसके वकीलों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग को अदालत ने दरकिनार करते हुए कहा, ऐसी निजी तस्वीरों को बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों जैसे सीलबंद लिफाफे के रिकॉर्ड पर लाना व्यक्ति की निजता और गरिमा का उल्लंघन और हनन है।

संपादकीय

सड़क सुरक्षा बोर्ड

किस तरह कुछ आवश्यक मामलों में भी समय पर कदम उठाने से बचा जाता है,इसका ही उदाहरण है लंबी देरी के बाद राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी होना। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि सात वर्ष की प्रतीक्षा के बाद इस बोर्ड का गठन किया जा सका और वह भी तब,जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बोर्ड के गठन में देरी को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त की। कायदे से इस बोर्ड का गठन 2019 में तभी कर दिया जाना चाहिए था, जब मोटर यान अधिनियम में संशोधन कर इसके लिए प्रविधान किए गए थे। इस बोर्ड के गठन में देरी यही बताती है कि हमारे नीति-नियंता सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के मामले में संवेदनशील नहीं।

इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि आखिरकार इस 20 सदस्यीय बोर्ड का गठन कर दिया गया,क्योंकि बात तब बनेगी,जब यह बोर्ड प्रभावी परिणाम देने में समर्थ भी होगा। इस बोर्ड के सदस्यों में सड़क इंजीनियरिंग और यातायात प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें विभिन्न राज्यों के परिवहन आयुक्त और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी भी होंगे।

यह बोर्ड केंद्र और राज्य सरकारों के साथ स्थानीय निकायों को यातायात प्रबंधन संबंधी तकनीकी सलाह और सहायता देने के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के सुरक्षित डिजाइन,निर्माण,रखरखाव आदि के न्यूनतम सुरक्षा मानक भी निर्धारित करेगा। इसके अतिरिक्त यह बोर्ड सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां बनाने के भी सुझाव देगा।

समझना कठिन है कि बेलगाम मार्ग दुर्घटनाओं के बाद भी सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन में देरी क्यों हुई? यह काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था,क्योंकि देश में वर्ष दर वर्ष मार्ग दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इन दुर्घटनाओं में मरने और घायल होने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। मार्ग दुर्घटनाओं के मामले में भारत का रिकार्ड बेहद खराब ही नहीं, बल्कि शर्मनाक भी है,क्योंकि देश में वाहनों की संख्या कई देशों से कम हैं। मार्ग दुर्घटनाओं के कारण किसी से छिपे नहीं।

खराब सड़कें,खटारा वाहन,अकुशल चालक,यातायात नियमों की अनदेखी आदि सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। क्या राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड ऐसे उपाय कर सकेगा,जिनसे इन कारणों का निवारण हो सके? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि जब तक मार्ग दुर्घटनाओं के जाने-पहचाने कारणों का निवारण करने में लापरवाही का परिचय देने वाले अधिकारियों और विभागों को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा,तब तक हालात बदलने वाले नहीं हैं। इसलिए और नहीं,क्योंकि सुरक्षित यातायात के लिए जैसी राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छाशक्ति चाहिए, उसका अभाव ही अधिक दिखता है।

मजबूत लोकतंत्र के लिये दागी नेताओं से मुक्ति जरूरी

ललित गर्ग
पटपड़गंज,
नई दिल्ली

भारतीय लोकतंत्र ने स्वतंत्रता के बाद अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति होने के साथ-साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य के साथ देश आर्थिक,तकनीकी और वैश्विक नेतृत्व की नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। किंतु यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी अर्थव्यवस्था,सैन्य क्षमता अथवा तकनीकी विकास में नहीं, बल्कि उसकी राजनीति और शासन व्यवस्था की नैतिकता में निहित होती है। यदि लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखना है तो राजनीति को अपराध,भ्रष्टाचार और स्वार्थ की गिरफ्त से मुक्त करना ही होगा। आजादी के बाद से लगभग हर सरकार ने भ्रष्टाचार-मुक्त शासन, पारदर्शी प्रशासन और स्वच्छ राजनीति का वादा किया। अनेक आयोग बने, कानून बने और चुनाव सुधारों की चर्चाएं भी हुईं,लेकिन जब भी कोई ठोस एवं प्रभावी सुधार लागू करने का प्रयास हुआ,राजनीतिक दलों ने अपने-अपने हितों के अनुसार उसका समर्थन अथवा विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक शुचिता का प्रश्न आज भी अधूरा है। विडंबना यह है कि अब तक कोई ऐसा खाका सामने नहीं आ सका है, जिससे सिर्फ स्वच्छ छवि के लोगों को ही जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिले। यह और बड़ी विडम्बना है कि जिस विषय पर पूरे राष्ट्र की सहमति होनी चाहिए,वही विषय राजनीतिक टकराव का माध्यम बन जाता है।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

आए दिन संसद और विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद चुने गए जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता तो जताई जाती है, मगर उसके हल को लेकर कोई ठोस पहल नहीं होती। संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता है और इस संबंध में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसी संदर्भ में भाजपा सरकार फिर से एक सौ तीसवें संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी में है, जिसके तहत प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को पाँच साल से ज्यादा सजा के प्रावधान वाले गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार किए जाने और लगातार तीस दिनों तक हिरासत में रखे जाने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। अगर विधेयक की जांच के बाद संयुक्त संसदीय समिति इसे अपनी मंजूरी दे देती है, तो संसद के मानसून सत्र में इस पर बहस की संभावना है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अगस्त में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में यह विधेयक पेश किया था। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई कई आपत्तियों के बाद इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था,लेकिन कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दलों ने अपनी चिंताओं को नजरअंदाज किए जाने की आशंका के मद्देनजर समिति का बहिष्कार कर दिया था।

निश्चित ही संसद और विधान सभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जन प्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। यदि कोई जनप्रतिनिधि हत्या,बलात्कार, भ्रष्टाचार,आतंकवाद अथवा संगठित अपराध जैसे गंभीर मामलों में लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में है, तो क्या वह जनता का प्रतिनिधित्व करने का नैतिक अधिकार बनाए रखता है? यह प्रश्न केवल कानूनी नहीं,बल्कि लोकतंत्र की नैतिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हालांकि इस प्रकार के कानून पर कई संवैधानिक प्रश्न भी उठते हैं। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को

तब तक निर्दोष मानता है जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए। केवल आरोप के आधार पर किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को पद से हटाना राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार भी बन सकता है। विपक्षी दलों की यह आशंका पूरी तरह निराधार नहीं कही जा सकती कि यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं होंगे तो सत्ता में बैठी सरकारें विरोधियों के विरुद्ध जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर सकती हैं। इसलिए किसी भी नए कानून में प्राकृतिक न्याय,न्यायिक समीक्षा और निष्पक्ष जांच की सुदृढ़ व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। लेकिन इन आशंकाओं के कारण सुधार की पूरी प्रक्रिया को रोक देना भी उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में सुधार का अर्थ किसी दल को लाभ या हानि पहुंचाना नहीं,बल्कि जनता के विश्वास को मजबूत करना है। यदि कानून संतुलित, पारदर्शी और न्यायसंगत हो तो वह लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि अधिक विश्वसनीय बनाता है।

भारत की राजनीति में अनेक ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जिन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए। बिहार में लालू प्रसाद यादव से लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तथा उनके कुछ मंत्रियों तक, विभिन्न राजनीतिक दलों के अनेक नेता ऐसे रहे हैं जो गंभीर आरोपों अथवा जेल में रहने के बावजूद सत्ता पर बने रहने का प्रयास करते रहे। यह किसी एक दल का प्रश्न नहीं है,लगभग सभी बड़े राजनीतिक दल समय-समय पर इस आलोचना के घेरे में रहे हैं। जेल से सरकार चलाने अथवा संवैधानिक पद पर बने रहने की मानसिकता लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं कही जा सकती। यह सही है कि कानून अपना कार्य करेगा और न्यायालय अंतिम निर्णय देगा, किंतु सार्वजनिक जीवन केवल कानूनी वैधता से नहीं चलता, उसका आधार नैतिक वैधता भी होती है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि केवल अधिकारों का नहीं,बल्कि आदर्शों का भी प्रतीक होता है। यदि उसके ऊपर गंभीर आरोप हों और वह फिर भी पद से चिपका रहे,तो जनता का लोकतांत्रिक विश्वास कमजोर पड़ता है। राजनीति में पद त्यागना पराजय नहीं,बल्कि नैतिक साहस का परिचायक होता है।

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है,उसमें आर्थिक प्रगति के साथ सुशासन,डिजिटल पारदर्शिता, भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन और जन भागीदारी पर विशेष बल दिया गया है। विकसित भारत केवल ऊंची इमारतों, एक्सप्रेस-वे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तेज आर्थिक विकास से नहीं बनेगा, वह तभी बनेगा जब शासन चलाने वाले व्यक्तियों की विश्वसनीयता भी उतनी ही मजबूत होगी। विश्वगुरु बनने की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्र की राजनीति भी विश्व के लिए आदर्श बननी चाहिए। आज आवश्यकता केवल कानून बदलने की नहीं,बल्कि राजनीतिक संस्कृति बदलने की भी है। राजनीतिक दलों को चुनावी टिकट देते समय उम्मीदवार के चरित्र, सार्वजनिक जीवन,सामाजिक सेवा और नैतिक छवि को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय कई बार राजनीतिक दलों से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का कारण सार्वजनिक करने को कह चुका है,किंतु व्यवहार में इसमें अपेक्षित परिवर्तन दिखाई नहीं देता। यदि राजनीतिक दल स्वयं आत्मानुशासन नहीं अपनाएंगे,तो केवल कानून से समस्या का समाधान संभव नहीं होगा। इसके साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में भी व्यापक सुधार अपेक्षित हैं। जन प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का वर्षों तक लंबित रहना लोकतंत्र के लिए घातक है। विशेष न्यायालयों द्वारा समयबद्ध सुनवाई,निष्पक्ष जांच और शीघ्र निर्णय की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि न निर्दोष व्यक्ति वर्षों तक संदेह के घेरे में रहे और न दोषी व्यक्ति कानून की तकनीकी जटिलताओं का लाभ उठाकर जनता का प्रतिनिधित्व करता रहे। लोकतंत्र की सफलता केवल संविधान से नहीं, बल्कि राजनीतिक चरित्र से सुनिश्चित होती है। जब तक राजनीति में नैतिकता,सेवा,त्याग और उत्तरदायित्व की भावना नहीं आएगी,तब तक भ्रष्टाचार और अपराध का दुष्चक्र पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, किंतु राष्ट्रीय हित से जुड़े सुधारों का विरोध केवल राजनीतिक लाभ-हानि के आधार पर नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रस्ताव में कमियां हैं तो उन्हें सुधारने के सुझाव दिए जाएं, लेकिन सुधार की दिशा को अवरुद्ध करना लोकतांत्रिक परिपक्वता का परिचायक नहीं माना जा सकता।

आज भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु भारत का स्वप्न है,तो दूसरी ओर राजनीति की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने की चुनौती भी है। इन दोनों लक्ष्यों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। आर्थिक विकास और नैतिक विकास समानांतर चलेंगे तभी राष्ट्र सशक्त बनेगा। समय की पुकार है कि सत्ता और विपक्ष दोनों दल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर लोकतंत्र की पवित्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। देश की राजनीति को आपराधिक छवि के लोगों से मुक्त करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए जो कानून बने, उसमें अपराधों की प्रकृति स्पष्ट किए जाने से लेकर ऐसे सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है, ताकि महज बदले या किसी सरकार को अस्थिर करने की मंशा से इसका दुरुपयोग न हो सके।

इस्तीफे की मांग और जिम्मेदार का अहसास,बनेगा लोकतंत्र रामबाण

केसी गुप्ता
द्वारका,दिल्ली

देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 13 दिनों से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है । इस आंदोलन में देश के जाने माने अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं। यह इस्तीफा युवा विद्यार्थियों के हक की लड़ाई है ।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

नीट तथा शिक्षा से जोड़े अनेकों पेपरों के समय समय पर लीक होने से युवाओं द्वारा निराशावंश किए गए सुसाइड से अनेकों घरों के चिराग़ बुझ गए। यह कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा मंत्री होने के नाते श्री धर्मेंद्र प्रधान की युवा पीढ़ी के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदारी दोनों ही बनती हैं। बड़ा सवाल यह है की देश के नेता जो जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं ,वह जनता के इस्तीफा मागने पर सीट छोड़ने से कतराते क्यों है ? क्या यह लोकतंत्र के विरोध नहीं ? किसी भी जिम्मेदार नेता को किसी भी लापरवाही या कारण से हुई अपने दायित्व में असफलता के लिए स्वयं आगे बढ़कर इस्तीफा दे देना चाहिए। इतिहास में और वर्तमान में कई देशों के नेताओं ने अपने दायित्व की पूर्ति ना होने पर स्वयं आगे बढ़कर इस्तीफा दिया है । जो एक सराहनीय कदम माना गया।

युवा पीढ़ी देश का भविष्य है। यदि किसे देश की युवा पीढ़ी नाखुश और निराश है तो वह देश विकसित कैसे हो सकता है ? युवा पीढ़ी के असंतोष और आक्रोश को समझना वर्तमान सरकार का दायित्व है। देश के युवा भीषण गर्मी में अपने हक के लिए झुलसते रहे तो यह चिंगारी आग बन सकती है । यह एक इस्तीफा देश के समस्त नेताओं प्रतिनिधियों में अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी ,सजगता, ईमानदारी,निष्ठा के अहसास को जगाने का रामबाण बनेगा । यह लोकतंत्र की विजय होगी ।

किरायेदार

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा

शहर के सबसे पुराने मुहल्ले में एक मकान था जिसकी दीवारें इतनी बूढ़ी हो चुकी थीं कि हर बारिश के बाद वे अपने भीतर का नमक बाहर निकालकर रोती थीं। लोग उसे भूतों का घर कहते थे, लेकिन वहाँ रहने वाला बूढ़ा आदमी हँसकर कहता, भूत तो उन घरों में रहते हैं जहाँ इंसान होना मर जाता है। उसका नाम कोई नहीं जानता था। बच्चे उसे बाबा कहते थे, दूधवाला उसे उधार कहता था,बिजली वाला उसे बकायेदार और नगर निगम वाला उसे अतिक्रमण। उसका अपना नाम जैसे सरकारी फाइलों के किसी पीले पन्ने में दम तोड़ चुका था। हर सुबह वह टूटी कुर्सी बाहर निकालकर बैठ जाता और राह चलते लोगों से पूछता,बेटा,आज इंसानियत किस गली से गुज़री थी, कहीं दिखी क्या? लोग मुस्कराकर आगे बढ़ जाते। एक दिन एक लड़का रुक गया। उसने पूछा, बाबा,आप रोज़ यही सवाल क्यों पूछते हैं? बाबा ने अपनी धुँधली आँखों में उतरती शाम को समेटते हुए कहा,क्योंकि कल तक जो मेरे पड़ोसी थे, आज वे मेरे मोबाइल नंबर तक से अनजान हो गए हैं। रिश्ते अब घंटियों की तरह हैं, बजते तभी हैं जब किसी को अपना काम हो।÷ लड़का चुप हो गया। हवा ने सूखे नीम से कुछ पत्ते गिराए। बाबा उन्हें उठाकर हथेली पर रखने लगा जैसे किसी बूढ़ी माँ के झड़ते बाल समेट रहा हो। उसने धीमे से कहा,पेड़ कम से कम गिरकर भी धरती का हाथ नहीं छोड़ते, इंसान तो खड़े खड़े भी साथ छोड़ देता है। सामने से गुजरते नेता का काफिला धूल उड़ाता निकल गया। बाबा मुस्कराया, देखो बेटा, धूल भी अब गाड़ियों के साथ चलती है,पैरों के साथ नहीं।

अगले दिन मोहल्ले में खबर फैली कि सरकार ने उस इलाके के विकास का नक्शा बना लिया है। लोग खुश थे। किसी को चौड़ी सड़क चाहिए थी, किसी को पार्क,किसी को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। बाबा चुपचाप अपनी दीवार सहला रहा था। तभी अधिकारी आए। एक ने नक्शा खोलकर कहा,बाबा,आपका मकान प्रगति के रास्ते में आ रहा है। बाबा ने मुस्कराकर पूछा,प्रगति किसकी होगी साहब, सड़क की या आदमी की? अधिकारी हँस पड़ा। भावुक मत बनिए। मुआवजा मिलेगा। बाबा ने दीवार पर टँगी अपनी पत्नी की धुँधली तस्वीर की ओर देखा और बोला,साहब,क्या आपकी फाइल में यादों की भी कोई कीमत लिखी है?दूसरा अधिकारी झुँझलाकर बोला, हम भावनाएँ नहीं नापते। बाबा ने उत्तर दिया,यही तो इस देश की सबसे बड़ी तरक्की है। अब सब कुछ नापा जाता है,बस आदमी नहीं। भीड़ तमाशा देख रही थी। किसी ने कहा, बाबा जिद्दी है। किसी ने कहा, बूढ़े लोग बदलाव नहीं चाहते। बाबा धीरे से बोला,बदलाव मुझे भी चाहिए बेटा। बस इतना कि आदमी फिर आदमी कहलाने लगे। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसे सुनने के लिए कान नहीं, दिल चाहिए था। मगर वहाँ दिलों की जगह मोबाइल कैमरे खुले हुए थे। हर चेहरा घटना रिकॉर्ड कर रहा था, कोई पीड़ा नहीं।

रात को वही लड़का फिर आया। उसने पूछा,बाबा,अगर घर टूट गया तो आप कहाँ जाएँगे? बाबा ने आकाश की ओर देखा। जहाँ से आया था, वहीं। आदमी आखिर रहता कहाँ है? ईंटों में या स्मृतियों में? लड़के ने कहा, मैं आपको अपने घर ले जाऊँगा। बाबा मुस्कराया। बेटा,जिस घर में बूढ़े को जगह देने के लिए पहले सोफा हटाना पड़े, वहाँ बूढ़ा नहीं जाता। लड़का रो पड़ा। तो मैं क्या करूँ? बाबा ने उसका सिर सहलाया। बस इतना करना कि जब तेरे पिता बूढ़े हों तो उन्हें कैलेंडर की पुरानी तारीख मत समझना। तभी सामने वाले मकान से तेज संगीत बजने लगा। जन्मदिन की पार्टी थी। इधर बाबा चुपचाप अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें कर रहा था।

नई संवैधानिक सर्जरी : सत्ता से अपराध की सीधी विदाई

- 30 दिन हिरासत,31 वें दिन इस्तीफा : सत्ता का नया कायदा
- युवा पीढ़ी का सपना साकार हो रहा है...स्वच्छ सत्ता का सपना

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

प्रो.आर.के.जैन
अरिजीत
बड़वानी,मध्यप्रदेश

भारतीय राजनीति की सबसे ऊंची कुर्सियों के लिए अब केवल जनादेश पर्याप्त नहीं रहेगा,बल्कि कानून की कसौटी पर खरा उतरना भी अनिवार्य होगा। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 (जो अगस्त 2025 में लोकसभा में पेश किया गया) इसी नई व्यवस्था का संकेत देता है। इसके अनुसार यदि प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ऐसे गंभीर अपराध में, जिसमें पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, लगातार तीस दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है,तो उसे इकतीसवें दिन पद छोड़ना होगा। इस्तीफा न देने पर उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह संशोधन केवल कानूनी बदलाव नहीं,बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति पर प्रहार है,जिसमें जेल से भी सत्ता संचालित होती रही। संदेश स्पष्ट है—लोकतंत्र में जनादेश सम्मान देता है, पर पद पर बने रहने का अधिकार अंततः कानून और जनविश्वास ही तय करेंगे।

इस विधेयक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने जवाबदेही को समय-सीमा से बांध दिया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित अवधि पूरी होते ही पद छोड़ना अनिवार्य होगा। मंत्रियों के मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल, प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन सलाह न आने पर भी पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। अर्थात अब संवैधानिक व्यवस्था किसी राजनीतिक निर्णय की बंधक नहीं रहेगी। यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के लिली थॉमस निर्णय की भावना को आगे बढ़ाता है,जिसने दोषसिद्धि पर तत्काल अयोग्यता का सिद्धांत स्थापित किया था। रेप्रेज़ेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट,1951 पहले से दोषसिद्ध जनप्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराता है,किंतु नया संशोधन जवाबदेही की शुरुआत दोषसिद्धि के बाद नहीं, बल्कि गंभीर मामलों में लंबी न्यायिक हिरासत से ही कर देता है। यही इसे अब तक की व्यवस्थाओं से अलग और अधिक प्रभावी बनाता है।

यदि यह संशोधन प्रभावी ढंग से लागू हुआ,तो राजनीति की कार्यसंस्कृति बदल सकती है। अपराधीकरण और भ्रष्टाचार पर इसका सीधा प्रहार होगा,क्योंकि गंभीर मामलों में लंबी न्यायिक हिरासत अब केवल कानूनी संकट नहीं, बल्कि सत्ता से विदाई का कारण भी बन सकती है। इससे स्वच्छ छवि वाले नेतृत्व को अवसर मिलेगा,ईमानदार युवाओं का भरोसा बढ़ेगा और जनता का विश्वास मजबूत होगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। शासन का ध्यान व्यक्तिगत मुकदमों से हटकर विकास और सुशासन पर केंद्रित रहेगा। उल्लेखनीय है कि यह स्थायी दंड नहीं है,न्यायिक राहत मिलने पर पुनर्नियुक्ति संभव होगी। इसलिए यह व्यवस्था प्रतिशोध नहीं,बल्कि सार्वजनिक पद की गरिमा और जवाब देही को सुरक्षित रखने का निवारक उपाय अधिक है। इसी कारण कुछ संवैधानिक विशेषज्ञ इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं।

सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या केवल लंबी न्यायिक हिरासत, बिना दोषसिद्धि के,किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को पद से हटाने का आधार बन सकती है, जबकि न्याय का मूल सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति को दोष सिद्ध होने तक निर्दोष मानता है। विपक्ष और अनेक विधि विशेषज्ञों को आशंका है कि जांच एजेंसियों पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ने पर यह प्रावधान विरोधियों को सत्ता से हटाने का हथियार बन सकता है। विशेषकर विपक्ष शासित राज्यों में इससे केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव बढ़ने की आशंका है। इसलिए इस संशोधन की वास्तविक कसौटी उसकी कठोरता नहीं,बल्कि निष्पक्ष और दुरुपयोग-मुक्त क्रियान्वयन होगी। इस बदलाव का असर केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि सरकारों की स्थिरता पर भी पड़ेगा। छोटे बहुमत वाली सरकारों में यदि मुख्यमंत्री या कई मंत्री एक साथ पद छोड़ने को विवश हुए, तो सत्ता का संतुलन बदल सकता है और नए राजनीतिक समीकरण उभर सकते हैं। समर्थकों का तर्क है कि यदि किसी सरकार की स्थिरता गंभीर मामलों में जेल में बंद नेताओं पर टिकी है,तो ऐसी स्थिरता लोकतंत्र के हित में नहीं मानी जा सकती। इसलिए असली चुनौती सरकार बचाने की नहीं,बल्कि शासन की विश्वसनीयता बनाए रखने की है। आखिर लोकतंत्र केवल सरकारों के टिके रहने से नहीं, बल्कि जनता के अटूट विश्वास से मजबूत होता है।

यह विधेयक भारतीय राजनीति को दो खेमों में बांट चुका है और जेपीसी में इस पर बहस जारी है। सत्तापक्ष इसे भ्रष्टाचार-मुक्त शासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम मानता है,जबकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर आघात बताता है। इसलिए संसदीय समिति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह सभी प्रावधानों की गहन समीक्षा कर दुरुपयोग रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करे। सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट कर चुका है कि सांसद और विधायक विशेषाधिकार प्राप्त शासक नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह जनसेवक हैं। अतः यह संशोधन तभी सफल माना जाएगा जब जवाबदेही और न्याय का संतुलन बना रहे। वर्तमान में जेपीसी इस विधेयक की जांच कर रही है और जुलाई 2026 के मध्य तक रिपोर्ट पेश करेगी।

महँगाई की मार

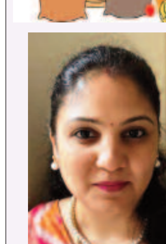

मोनिका डागा
आनंद,
चेन्नई,
तमिलनाडु

रोज मिल रहे हैं बस नए-नए ज़ख्म,
किसे कहें अपना दर्द खुलकर हम,
आम आदमी तो टूट रहा है हर दिन,
दैनिक जीवकोपार्जन है बड़ा कठिन ।

कमर तोड़ती हुई ये महँगाई की मार,
चक्रवृद्धि ब्याज सी दरें बढ़ती तीव्र धार,
आमदनी होती जा रही धीरे-धीरे कम,
महँगाई ने भैया कर रखा नाक में दम ।

सरकारें बस बदलती और बनती है नई,
पर महँगाई पर अंकुश नहीं लगाता कोई,
आम आदमी को देते हैं झाँसा अक्सर,
सब स्वविकास की दौड़ में है बस तत्पर
।

सोना-चाँदी ख्वाबों में भी
नहीं खरीद सकें,
पहले दाल-रोटी तो
नसीब से पूरी मिल सकें,
आम आदमी केवल
बोझा ढोता रहता सारा ,
पेट्रोल गैस राशन तेल
सबने बार-बार मारा ।

गरीबी की रेखा से है
ऊपर पर अमीर कहाँ,
तड़पता खड़ा उसी बिन्दु पर
बरसों से वहाँ,
चिंताओं के घेरे में
व्याकुल किस्मत को कोसें,
जीवन आनंद मिल सकता कभी क्या उसे ।

अमीरों को नहीं पर पड़ता हैं ज्यादा फर्क,
आम आदमी देखता
जीवन को होते नरक,
बस चुनावों के समय
बनाया जाता महाराजा,
काम निकलते ही
सरकारें बजाती उसका बाजा ।

सभ्यता के अंत की शुरुआत,लालच से भरे युद्ध

संजीव ठाकुर,रायपुर छत्तीसगढ़

मानव सभ्यता ने हजारों वर्षों की यात्रा में ज्ञान, विज्ञान,संस्कृति और लोकतंत्र के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता,अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा और संचार के क्षेत्र में मानव ने ऐसी उपलब्धियाँ अर्जित की हैं जिनकी कल्पना भी कभी असंभव मानी जाती थी। किंतु विडंबना यह है कि जितनी तेजी से विज्ञान आगे बढ़ा है,उतनी ही तीव्रता से सत्ता,वर्चस्व और स्वार्थ की राजनीति भी विकसित हुई है। आज विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध की विभीषिका यह संकेत दे रही है कि मनुष्य ने तकनीक तो आधुनिक बना ली,परंतु अपनी चेतना को अभी भी संकीर्ण स्वार्थों से मुक्त नहीं कर पाया। आज अमेरिका,रूस, चीन, इज़राइल, ईरान,उत्तर कोरिया तथा अनेक क्षेत्रीय शक्तियाँ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शक्ति-प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा में लगी हुई हैं। कहीं आर्थिक प्रतिबंध हथियार बन रहे हैं, कहीं व्यापारिक युद्ध, कहीं साइबर आक्रमण,तो कहीं मिसाइलों और ड्रोन की वर्षा। ऐसा प्रतीत होता है कि वैश्विक राजनीति का मूल उद्देश्य मानव कल्याण नहीं, बल्कि प्रभुत्व स्थापित करना बन गया है।

रूस-यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष का प्रभाव सीमित नहीं रहता। लाखों लोग विस्थापित हुए,हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ,ऊर्जा की कीमतें बढ़ीं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा। इसी प्रकार मध्य-पूर्व में इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव केवल दो देशों का विवाद नहीं, बल्कि पूरे विश्व की सामरिक स्थिरता को प्रभावित करने वाला प्रश्न बन चुका है। विश्व की महाशक्तियाँ अपने-अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की बार-बार कहते रहे हैं कि स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा अधिकार है और उसकी रक्षा हर कीमत पर की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में युद्ध समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की है, किंतु साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों और सहयोगियों की सुरक्षा से पीछे नहीं हटेगा। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इज़राइल अपने अस्तित्व और सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अली ख़ामेनेई का स्पष्ट संदेश रहा है कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। हर राष्ट्र स्वयं को सही मानता है और अपने हितों की रक्षा को सर्वोपरि रखता है। किंतु जब संवाद की जगह शक्ति और प्रतिशोध ले लेते हैं,तब विश्व शांति सबसे बड़ी कीमत चुकाती है।

आज युद्ध का स्वरूप भी बदल चुका है। पहले युद्ध सीमाओं पर सैनिक लड़ते थे,अब अर्थव्यवस्थाएँ, तकनीक,साइबर नेटवर्क,कृत्रिम बुद्धिमत्ता,उपग्रह और सूचना तंत्र भी युद्ध के हथियार बन चुके हैं। व्यापारिक प्रतिबंध, सेमीकंडक्टर तकनीक पर नियंत्रण,दुर्लभ खनिजों की प्रतिस्पर्धा और ऊर्जा संसाधनों पर कब्ज़े की होड़ इस बात का प्रमाण हैं कि आधुनिक युद्ध केवल बंदूकों से नहीं लड़े जाते।

परमाणु हथियारों की बढ़ती संख्या विश्व के लिए सबसे बड़ा संकट है। आज विश्व में हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं। यदि किसी भी कारण से परमाणु संघर्ष प्रारंभ हुआ,तो उसका प्रभाव केवल युद्धरत देशों तक सीमित नहीं रहेगा। जलवायु परिवर्तन,परमाणु विकिरण, खाद्य संकट और वैश्विक आर्थिक पतन पूरी मानवता को प्रभावित करेंगे। महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था, आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। प्रतिशोध कभी स्थायी शांति नहीं ला सकता। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने चेतावनी दी थी मुझे नहीं पता तीसरा विश्वयुद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा,लेकिन चौथा विश्वयुद्ध पत्थरों और लाठियों से लड़ा जाएगा। यह कथन केवल कल्पना नहीं, बल्कि परमाणु युद्ध के संभावित परिणामों का वैज्ञानिक आकलन है।पूर्व संयुक्त राष्ट महासचिव बान की-मून ने कहा था, शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि न्याय, समानता और सहयोग की उपस्थिति है।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

कलेक्टर से शिकायत के बाद डीईओ ने बैठाई जांच...

3 दिन में मांगी रिपोर्ट,अभिभावकों को WhatsApp पर भेजी जा रही निजी प्रकाशकों की सूची....

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सरकार जहां कक्षा 10 वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं सरगुजा के कई निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर इस पूरी व्यवस्था को दरकिनार कर निजी प्रकाशकों और चुनिंदा पुस्तक विक्रेताओं के साथ कथित कमीशनखोरी का नेटवर्क चलाने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि अभिभावकों को सरकारी किताबों के बजाय महंगे निजी प्रकाशनों की पुस्तकें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शिकायत कलेक्टर तक पहुंचने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तीन सदस्यीय जांच दल गठित कर तीन दिन के भीतर प्रतिवेदन तलब किया है।

शिकायतकर्ता पार्षद आलोक दुबे ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया है कि अधिकांश निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल बच्चों के अभिभावकों को WhatsApp पर निजी प्रकाशकों की पुस्तकों की सूची भेज रहे हैं और उन्हें केवल चिन्हित दुकानों से ही किताबें खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। इससे अभिभावकों पर हजारों रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है,जबकि इन्हीं कक्षाओं की एससीईआरटी की पुस्तकें शासन द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पहली कक्षा का बुक सेट 1650 से 2000 रुपये...पांचवीं का 5000 रुपये तक...

शिकायत में दावा किया गया है कि पहली कक्षा के एक निजी स्कूल के पुस्तक सेट की कीमत करीब 1650 से 2000 रुपये तक है,जबकि पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लगभग 5000 रुपये तक की किताबें खरीदी जा रही हैं। आरोप है कि इस व्यवस्था से स्कूल और पुस्तक विक्रेता दोनों को कमीशन मिलता है।

माइलस्टोन स्कूल का नाम भी शिकायत में...

शिकायतकर्ता ने एक निजी स्कूल द्वारा भेजी गई कथित पुस्तक सूची का उल्लेख करते हुए कहा है कि एससीईआरटी की निःशुल्क पुस्तकों के साथ निजी प्रकाशकों की अतिरिक्त किताबें भी अनिवार्य बताई जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठाया गया है कि जब एक ही विषय की दो-दो किताबें खरीदी जा रही हैं,तो आखिर पढ़ाई किस पुस्तक से हो रही है? यदि निजी किताबों से पढ़ाई हो रही है तो सरकारी किताबों का औचित्य क्या रह जाता है, और यदि सरकारी किताबों से पढ़ाई हो रही है तो अभिभावकों से हजारों रुपये क्यों वसूले जा रहे हैं?

कॉपियां खोलें तो सामने आ जाएगी सच्चाई : शिकायत में कहा गया है कि जांच दल यदि बच्चों की कॉपियां और कक्षा में उपयोग होने वाली पुस्तकों का मिलान कर ले तो तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तविक पढ़ाई किस पुस्तक से कराई जा रही है। इससे यह भी सामने आ जाएगा कि कहीं सरकारी पुस्तकों को केवल औपचारिकता तक सीमित तो नहीं कर दिया गया है।

डीईओ ने गठित की जांच टीम

मामले को गंभीर मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने तीन अधिकारियों की जांच टीम गठित कर शिकायत के प्रत्येक बिंदु की जांच के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से तीन दिन के भीतर विस्तृत जांच प्रतिवेदन मांगा गया है।

उठ रहे बड़े सवाल

- जब सरकार निःशुल्क पुस्तकें दे रही है तो निजी किताबें खरीदना क्यों अनिवार्य बनाया जा रहा है?
- क्या स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं के बीच कमीशन का खेल चल रहा है?
- एक ही विषय की दो-दो किताबों की जरूरत किस आधार पर तय की गई?
- यदि सरकारी किताबों से पढ़ाई नहीं हो रही तो शासन की योजना का लाभ किसे मिल रहा है?
- क्या शिक्षा विभाग अब तक इस व्यवस्था से अनजान था या शिकायत का इंतजार कर रहा था?

जांच तय करेगी सच,लेकिन सवाल गंभीर

यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डालने का मामला नहीं होगा,बल्कि शासन की निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना की भावना को कमजोर करने और शिक्षा के नाम पर कथित आर्थिक लाभ कमाने का भी गंभीर मामला माना जाएगा। अब सबकी नजर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की जांच पर है कि कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रहती है या वास्तव में जिम्मेदारों पर शिकंजा कसता है।

मंच पर माला पहनाने से शुरू हुआ विवाद,महिला सरपंच के परिवार का सामाजिक बहिष्कार

खेरवार समाज ने एक साल तक हुक्का-पानी बंद करने का फरमान सुनाया,पीड़ित परिवार ने भाजपा नेता के खिलाफ थाने में की शिकायत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रघुनाथनगर थाना क्षेत्र के हरिगवां गांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान महिला सरपंच को मंच पर माला पहनाने की घटना अब सामाजिक विवाद में बदल गई है। खेरवार समाज ने महिला सरपंच और उनके पूरे परिवार का एक वर्ष के लिए सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। समाज के इस फैसले के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पीड़ित परिवार ने भाजपा नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है,जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार करीब 10 दिन पहले हरिगवां ग्राम पंचायत में स्थानीय भाजपा नेताओं की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मंच पर महिला सरपंच सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता मौजूद थे। स्वागत के क्रम में भाजपा नेता मंशाराम साहू ने महिला सरपंच को मंच पर माला पहनाकर सम्मानित किया। इसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कार्यक्रम के दौरान ही महिला सरपंच के पति ने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध जताया। उनका कहना था कि किसी पुरुष द्वारा मंच पर महिला को माला पहनाना सामाजिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। इसके बाद मामला खेरवार समाज की बैठक तक पहुंचा, जहां समाज के लोगों ने महिला सरपंच और उनके पूरे परिवार का एक वर्ष के लिए सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया। समाज के फैसले के तहत परिवार का हुक्का-पानी बंद कर दिया गया है। साथ ही यह शर्त भी रखी गई है कि निर्धारित सामाजिक दंड पूरा करने के बाद ही परिवार को दोबारा समाज में शामिल किया जाएगा। इस निर्णय के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में बहस छिड़ गई है। कई लोग इसे सामाजिक परंपरा का मामला बता रहे हैं, जबकि कई इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और व्यक्तिगत अधिकारों के विपरीत मान रहे हैं। सामाजिक बहिष्कार से आहत महिला सरपंच और उनके परिवार ने अब कानूनी रास्ता अपनाया है। परिवार का कहना है कि सार्वजनिक कार्यक्रम में सम्मानित करना आयोजकों की जिम्मेदारी होती है। यदि माला पहनाना उचित नहीं था तो भाजपा नेता को माला हाथ में देकर सम्मान करना चाहिए था। परिवार ने भाजपा नेता मंशाराम साहू के खिलाफ रघुनाथनगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पंचायत कार्यों में कथित वसूली जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दूसरी ओर भाजपा नेता की ओर से भी मामले में अपना पक्ष रखा गया है। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों ने थाने में लिखित शिकायत दी है। अब पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। शुक्रवार को रघुनाथनगर थाना प्रभारी धीरेंद्र तिवारी स्वयं हरिगवां गांव पहुंचे और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए। थाना प्रभारी धीरेंद्र तिवारी ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत प्राप्त हुई है। जांच के दौरान कार्यक्रम की परिस्थितियों, समाज द्वारा लिए गए निर्णय और शिकायतों में लगाए गए आरोपों की पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर सामाजिक परंपराओं, महिलाओं के सम्मान, जनप्रतिनिधियों की गरिमा और सामाजिक बहिष्कार जैसे मुद्दों पर चर्चा तेज कर दी है। अब सभी की नजर पुलिस जांच और उसके निष्कर्ष पर टिकी हुई है।

इंजीनियरिंग कॉलेज के विकास को 14.08 करोड़ की मंजूरी

दो नए अकादमिक भवन, 100 सीटर बालिका छात्रावास व आधुनिक प्रयोगशालाएं बनेंगी,16 साल पुरानी मांग होगी पूरी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, अंबिकापुर के अधोसंरचनात्मक विकास के लिए राज्य शासन ने 14 करोड़ 8 लाख 22 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से दो नए जी+1 शैक्षणिक भवन, 100 सीटर बालिका छात्रावास, बाउंड्री वॉल, पार्किंग शेड तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा। निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा एकीकृत निविदा के माध्यम से कराया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार पहले भवन में सिविल, मैकेनिकल और माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग संचालित होंगे, जबकि दूसरे भवन में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एमबीए विभाग स्थापित किए जाएंगे। सभी विभागों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाओं का भी निर्माण होगा। महाविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि वर्ष 2010 से लंबित अधोसंरचना विकास योजना को इस स्वीकृति से गति मिलेगी।

बाउंड्री वॉल के निर्माण के बाद परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में भी कार्रवाई आसान होगी। साथ ही महाविद्यालय परिसर का स्वरूप अधिक आधुनिक और सुव्यवस्थित होगा। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र भेजने के बाद यह स्वीकृति मिली है।

करैत के डसने से 2 सगे भाइयों समेत 3 की मौत

बलरामपुर में एक ही खाट पर सो रहे थे तीन भाई, दो को डसा करैत; जशपुर की महिला ने भी इलाज के दौरान तोड़ा दम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग में सर्पदंश की अलग-अलग घटनाओं में दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। तीनों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रघुनाथनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पीपरसोत के तुर्रापारा निवासी बिरसपत नगेसिया के तीन बेटे

विकेश (11), विकास (9) और विक्रांत (3) गुरुवार रात एक ही खाट पर सो रहे थे। देर रात सबसे छोटे बेटे विक्रांत के रोने पर परिजन पहुंचे तो वह कान की ओर इशारा कर रहा था। इसी दौरान विकास ने भी बाएं हाथ की उंगली में किसी चीज के काटने की बात कही। परिजनों ने बच्चों को खाट से हटाकर देखा तो वहां करैत सांप मिला। विक्रांत के दाहिने कान और विकास की बाएं हाथ की उंगली में सांप ने डस लिया था। परिजन दोनों बच्चों को पहले जिला अस्पताल बलरामपुर ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया गया।

इलाज के दौरान दोनों भाइयों ने तोड़ा दम

शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे दोनों बच्चों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने विकास को मृत घोषित कर दिया। वहीं आईसीयू में भर्ती विक्रांत ने भी कुछ घंटे बाद दम तोड़ दिया।

जशपुर की महिला की भी गई जान

दूसरी घटना जशपुर जिले के ग्राम दोकड़ा की है। यहां सेबेस्तिया लोमी खेस (43) को 30 जून की रात घर में चटाई पर सोते समय करैत सांप ने घुटने के नीचे दाहिने पैर में डस लिया था। सांप को मारने के बाद परिजन उसे फरसाबहार अस्पताल ले गए। वहां से रेफर किए जाने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई।

8 और 9 जुलाई से शुरू होगी हाई व हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा,जिले के 22 केंद्रों पर होगी परीक्षा

संवाददाता-
बलरामपुर,03 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य (अवसर) परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। हायर सेकेंडरी की परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई 2026 तक तथा हाईस्कूल की परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षाएं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक संचालित होंगी। जिले में परीक्षा के लिए कुल 22 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी, निरीक्षण तथा अनुचित साधनों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए अपर कलेक्टर चेतन बोरघरिया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

नकटी बुलडोजर कार्रवाई पर सियासत तेज : अंबिकापुर में कांग्रेस ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला,मानसून में गरीबों के घर तोड़ने पर सरकार को घेरा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

रायपुर के माना क्षेत्र स्थित नकटी गांव में विधायक कॉलोनी निर्माण के लिए किए गए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गई है। शुक्रवार को इसी कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने अंबिकापुर के घड़ी चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए बुलडोजर कार्रवाई को गरीब विरोधी और अमानवीय बताया। कांग्रेस का आरोप है कि सोमवार को रायपुर के माना स्थित नकटी गांव में प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 85 मकानों पर बुलडोजर चलाया। पार्टी का दावा है कि इनमें 32 मकान इंदिरा आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए थे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बरसात के मौसम में गरीब परिवारों के सिर से छत छीन लेना सरकार की असंवेदनशीलता का परिचायक है।

टी.एस. सिंहदेव के दौरे के बाद प्रदेशव्यापी विरोध : कांग्रेस ने इस पूरे मामले को प्रदेशव्यापी आंदोलन का रूप दिया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव गुरुवार को नकटी गांव पहुंचे थे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और घटनास्थल का निरीक्षण किया। दौरे के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई को 'अमानवीय और असंवेदनशील' बताते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के पुतला दहन का निर्णय लिया। इसी क्रम में सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के घड़ी चौक पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया।

मुख्यमंत्री पर साधा निशाना : कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर भी राजनीतिक हमला बोला। बालकृष्ण पाठक ने कहा कि प्रदेश में जब भी जनता महंगाई, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था या प्रशासनिक फैसलों को लेकर सवाल उठाती है, तब सरकार के पास 'मोदी की गारंटी' के अलावा कोई जवाब नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रदेश की जनता के प्रति उनकी स्वयं की क्या गारंटी है।

'भाजपा के भीतर भी असंतोष' का दावा : कांग्रेस नेताओं ने यह भी दावा किया कि इस कार्रवाई को लेकर भाजपा के अंदर भी असंतोष है। उनका कहना था कि भाजपा के ही जनप्रतिनिधि सरकार और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि यह निर्णय व्यापक सहमति के बिना लिया गया।

आश्वासन के बाद भी चली कार्रवाई...

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि नकटी गांव के लोगों को स्थानीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भरोसा दिलाया था कि बारिश के दौरान किसी भी परिवार का घर नहीं तोड़ा जाएगा। इसके बावजूद प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्रवाई कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने ही जनप्रतिनिधियों के आश्वासनों का सम्मान नहीं कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट की भावना के विपरीत कार्रवाई का आरोप

कांग्रेस ने दावा किया कि मानसून के दौरान लोगों के मकान तोड़ना सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों और मानवीय सिद्धांतों की भावना के विपरीत है। बालकृष्ण पाठक ने कहा कि यदि किसी स्थान से अतिक्रमण हटाना आवश्यक भी हो, तो प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होती है। बिना समुचित व्यवस्था किए गरीबों के घर उजाड़ना असंवेदनशील प्रशासनिक रवैया है।

पुलिस से हुई झूमा-झटकी

मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कुछ देर तक धक्का-मुक्की और झूमा-झटकी की स्थिति बनी रही। हालांकि बाद में कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर प्रदर्शन समाप्त किया।

बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद

प्रदर्शन में जे.पी. श्रीवास्तव, हेमंत सिन्हा, संजय विश्वकर्मा, मोहम्मद इस्लाम, इंद्रजीत सिंह धंजल, सत्येंद्र तिवारी, जगन्नाथ कुशवाहा, नुरुल अमीन सिद्दीकी, दुर्गेश गुप्ता, प्रशांत सिंह 'चीकू', सरोज साहू, ए.पी. शांडिल्य, डॉ. लालचंद यादव, अतुल तिवारी, रसीद अहमद, संजय सिंह, शांतनु मुखर्जी, जमील खान, लोकेश कुमार, अमित तिवारी 'राजा', विकल झा, जीवन यादव, धर्मेंद्र ताम्रकार, चंद्रप्रकाश सिंह, रजनीश सिंह, नीतीश चौरसिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

वन विभाग के 125 अधिकारियों को आरटीआई कानून का प्रशिक्षण,सूचना के अधिकार पर हुई कार्यशाला

मुख्य वन संरक्षक दिलराज प्रभाकर के निर्देशन में आयोजित प्रशिक्षण,डॉ. डी.के. सोनी ने बताए अधिनियम के कानूनी व व्यावहारिक पहलू

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा वन वृत्त के सामान्य टेरिटोरियल एवं वन्यजीव प्रभागों के जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम-2005 पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम के नवीनतम प्रावधानों, कानूनी प्रक्रियाओं तथा सूचना आवेदनों के समयबद्ध और प्रभावी निराकरण के संबंध में प्रशिक्षित करना था। मुख्य वन संरक्षक दिलराज प्रभाकर के निर्देशन में आयोजित इस कार्यशाला में सरगुजा संभाग के छह वन मंडलों से जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी,कंप्यूटर ऑपरेटर एवं शाखा प्रभारी सहित लगभग 125 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के मुख्य संसाधन व्यक्ति एवं प्रशिक्षक आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता डॉ. डी.के. सोनी ने

सूचना का अधिकार अधिनियम की विभिन्न धाराओं,सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, अपील व्यवस्था, समय-सीमा तथा न्यायालयों एवं सूचना आयोगों के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए अधिनियम के व्यावहारिक पक्षों पर भी विस्तार से चर्चा की। मुख्य वन संरक्षक दिलराज प्रभाकर ने कहा कि आरटीआई अधिनियम वर्ष 2005 से लागू है और समय-समय पर अधिकारियों का प्रशिक्षण आवश्यक होता है। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग एक वर्ष से इस विषय पर कोई कार्यशाला आयोजित नहीं हुई थी, जबकि इस दौरान कई नए व्यावहारिक और कानूनी पहलू सामने आए हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों के लिए यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कोरिया (बैकुंठपुर) की वनमंडलाधिकारी प्रभाकर खलखो ने कहा कि आरटीआई को लेकर आम नागरिकों के साथ-साथ कई बार अधिकारियों के बीच भी भ्रांतियां रहती हैं। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम सूचना मांगने वाले और सूचना उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों के बीच बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होते हैं, जिससे समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराने और अनावश्यक विवादों से बचने में मदद मिलती है। कार्यशाला में उपस्थित वनमंडलाधिकारियों, एसडीओ एवं रेंजरों ने प्रशिक्षण को उपयोगी बताते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता जताई।

18 दिन बाद भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं,आखिर क्या उच्च अधिकारी मान चुके हैं कि कोई लापरवाही नहीं हुई ?

नौगई हत्याकांड : परिजनों की शिकायत के बाद भी नामजद पुलिस अधिकारी यथावत,विभागीय जांच पर उठे सवाल

- 18 दिन बाद भी शिकायत में नामित अधिकारी-कर्मचारी पद पर बरकरार...
- नौगई हत्याकांड : घटना से कथित आत्मसमर्पण तक पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में...
- परिजनों की विभागीय जांच और स्थानांतरण की मांग पर अब तक नहीं हुआ फैसला...
- 18 दिन बाद भी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं, आखिर किसका संरक्षण...
- परिजनों के आवेदन के बावजूद विभागीय जांच और स्थानांतरण पर चुप्पी...
- क्या नौगई हत्याकांड में पुलिस की भूमिका पर पर्दा डालने की कोशिश...
- सीबीआई जांच को मिली मंजूरी के बाद अब पुलिस की भूमिका भी जांच के घेरे में लाने की मांग... तेज,घटना से लेकर कथित आत्मसमर्पण तक उठ रहे सवाल...

रवि सिंह
कोरिया,03 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम नौगई में 16-17 जून की दरम्यानी रात हुए तिहरे हत्याकांड को 18 दिन बीत चुके हैं, इस दौरान तीन लोगों की दर्दनाक मौत, दो लोगों का गंभीर रूप से घायल होना,नौ आरोपियों की गिरफ्तारी, चार आरोपियों के कथित आत्मसमर्पण की कहानी और अंततः सीबीआई जांच की अधिसूचना तक कई बड़े घटनाक्रम सामने आए, लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल आज भी अनुत्तरित है की क्या इस जघन्य हत्याकांड में पुलिस की भूमिका पूरी तरह निष्पक्ष थी? यदि नहीं, तो जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर पीड़ित परिवार ने सवाल उठाए हैं, उन पर अब तक विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? घटना के बाद से पीड़ित परिवार लगातार यह कहता रहा है कि केवल आरोपियों को गिरफ्तार करना पर्याप्त नहीं है, यदि किसी स्तर पर पुलिस की लापरवाही, गलत निर्णय, कर्तव्य में शिथिलता या किसी प्रकार का संरक्षण सामने आता है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसी उद्देश्य से परिवार ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और सीआईडी के पुलिस महानिरीक्षक को विस्तृत आवेदन देकर विभागीय जांच की मांग की थी,इसके बावजूद 18 दिन बाद भी शिकायत में नामित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कोई स्पष्ट विभागीय कार्रवाई या स्थानांतरण सामने नहीं आया है।

घटना से पहले तनाव की जानकारी थी, फिर भी क्यों नहीं रोकी जा सकी वारदात?-परिजनों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस स्वयं स्वीकार कर चुकी थी कि दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था और तनाव की स्थिति बनी हुई थी,सुबह विवाद की सूचना थाने तक पहुंची,दोनों पक्षों को लेकर पुलिस सक्रिय रही,समझौते के प्रयास भी हुए, लेकिन इसके बावजूद रात में ऐसी भयावह वारदात हो गई जिसमें एक परिवार के पांच लोगों पर हमला हुआ, तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि पुलिस को पहले से विवाद की जानकारी थी तो क्या पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी? क्या दोनों पक्षों की समान रूप से निगरानी की गई? क्या संभावित हिंसा को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए? यदि नहीं,तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

थाना प्रभारी की भूमिका पर भी उठे सवाल-पीड़ित परिवार द्वारा दिए गए आवेदन में थाना प्रभारी सोनहत की भूमिका की विभागीय जांच की मांग की गई है,परिवार का कहना है कि जिस समय क्षेत्र में तनाव चरम पर था और बड़ी घटना की आशंका जताई जा रही थी,उसी समय थाना प्रभारी किसी अन्य कार्य से मुख्यालय से बाहर थे,परिजनों का कहना है कि यह जांच का विषय है कि उस समय थाना प्रभारी क्षेत्र से बाहर क्यों थे,उन्हें किस कार्य के लिए भेजा गया था और क्या उस परिस्थिति में थाना छोड़ना उचित था? यदि किसी स्तर पर निर्णय में त्रुटि हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

प्रभार संभाल रहे पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग- घटना के समय थाना का प्रभार संभाल रहे सब-इंस्पेक्टर राजाराम राठिया सहित उस समय ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की मांग आवेदन में की गई है, परिवार का कहना है कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की प्रतिक्रिया क्या रही, पुलिस कितनी देर में मौके पर पहुंची,किन परिस्थितियों में कार्रवाई हुई और क्या कहीं कोई लापरवाही हुई थी, हालांकि राजाराम राठिया को बाद में हटाए जाने की जानकारी सामने आई, लेकिन परिजनों का कहना है कि यदि जिम्मेदारी केवल एक अधिकारी की नहीं थी तो अन्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच आवश्यक है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की भूमिका भी जांच के दायरे में लाने की मांग-परिवार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेखा चौबे की भूमिका की भी विभागीय जांच की मांग की है,आवेदन में कहा गया है कि घटना के दौरान और उसके बाद वरिष्ठ स्तर पर लिए गए निर्णयों की समीक्षा आवश्यक है, परिवार का मानना है कि इतनी गंभीर घटना में केवल थाना स्तर की जांच पर्याप्त नहीं होगी,बल्कि पूरे कमांड सिस्टम की समीक्षा होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस स्तर पर क्या निर्णय लिए गए और उनमें कोई चूक तो नहीं हुई।

कथित आत्मसमर्पण की कहानी पर भी उठे सवाल-घटना के बाद चार आरोपियों के कथित आत्मसमर्पण को लेकर भी विवाद सामने आया, पीड़ित परिवार ने अपने आवेदन में मांग की है कि आत्मसमर्पण की पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराई जाए,परिवार चाहता है कि यह स्पष्ट किया जाए कि आरोपियों ने वास्तव में आत्मसमर्पण किया था या उन्हें पुलिस ने पहले से हिरासत में लिया था,यदि आत्मसमर्पण हुआ तो उसकी प्रक्रिया क्या थी और क्या वह पूरी तरह विधिसम्मत थी।

सीडीआर और मोबाइल लोकेशन की जांच की मांग...

परिजनों ने आवेदन में यह भी मांग की है कि पूरे घटनाक्रम से जुड़े मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर),मोबाइल लोकेशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कराई जाए, परिवार का कहना है कि इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना से पहले और बाद में किन-किन लोगों के बीच संपर्क हुआ, किस स्तर पर बातचीत हुई और घटनाक्रम की वास्तविक श्रृंखला क्या थी।

स्थानांतरण की मांग...ताकि जांच प्रभावित न हो...

परिवार ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण की भी मांग की है, आवेदन में प्रधान आरक्षक नवीन दत्त तिवारी (एमसीबी), थाना प्रभारी विनोद पासवान (सोनहत) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेखा चौबे (कोरिया) का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया गया है कि जांच पूरी होने तक इन्हें वर्तमान पदस्थापना से हटाकर सरगुजा संभाग के अन्य जिलों या आवश्यकतानुसार अन्यत्र पदस्थ किया जाए, परिजनों का तर्क है कि यदि जिन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, वे उसी क्षेत्र में पदस्थ रहेंगे तो जांच प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी।

18 दिन बाद भी नहीं हुई विभागीय कार्रवाई...

घटना के 18 दिन बाद भी शिकायत में नामित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध किसी विभागीय कार्रवाई या स्थानांतरण की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है,इसी कारण अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या उच्च पुलिस अधिकारियों ने प्रारंभिक स्तर पर यह मान लिया है कि इस पूरे मामले में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हुई, या फिर विभागीय जांच अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है।

सीबीआई जांच से बढ़ी उम्मीदें...

राज्य शासन द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (सीबीआई) को जांच का अधिकार दिए जाने के बाद पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि अब पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी,परिवार का कहना है कि सीबीआई यदि घटना से पहले की परिस्थितियों, पुलिस की तैयारियों, घटना के दौरान हुई कार्रवाई,घटना के बाद की विवेचना तथा कथित आत्मसमर्पण सहित पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच करेगी तो वास्तविक तथ्य सामने आ सकेंगे।

अब सबसे बड़ा सवाल...

नौगई तिहरे हत्याकांड अब केवल हत्या के एक मामले तक सीमित नहीं रह गया है,यह पुलिस की जवाबदेही,प्रशासनिक निर्णयों और न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता से जुड़ा मामला भी बन गया है, अब जबकि सीबीआई जांच का मार्ग प्रशस्त हो चुका है,सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या केवल आरोपियों की भूमिका की जांच होगी,या फिर उन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी निष्पक्ष रूप से जांची जाएगी जिनके संबंध में पीड़ित परिवार ने विभागीय जांच की मांग की है? पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी लड़ाई केवल दोषियों को सजा दिलाने की नहीं,बल्कि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाने की है,उनका मानना है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही, कर्तव्य में चूक या प्रक्रिया संबंधी त्रुटि हुई है, तो उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और जनता का कानून व्यवस्था पर विश्वास बना रहे।

जमीन मापी करने पहुंचे पटवारी से मारपीट,थाने में शिकायत

सेलरा गांव में सीमांकन के दौरान विवाद, पटवारी संघ ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सेलरा में जमीन की मापी (सीमांकन) करने पहुंचे एक पटवारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद पटवारी ने पटवारी संघ के पदाधिकारियों के साथ लखनपुर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार लखनपुर हल्का क्षेत्र के पटवारी सुबोध लकड़ा ग्राम पंचायत सेलरा में जमीन के बंटवारे एवं मापी की कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनसे विवाद करते हुए मारपीट कर दी। घटना के बाद राजस्व अमले में नाराजगी है। घटना की जानकारी मिलते ही पटवारी संघ के पदाधिकारी लखनपुर थाना पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। संघ का कहना है कि पटवारी शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। ऐसे में उनके साथ मारपीट की घटना गंभीर है और आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

कोटवारों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन,नियमितीकरण व वेतन वृद्धि समेत कई मांगें उठाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़, अंबिकापुर के अध्यक्ष सुरेश कुमार के नेतृत्व में कोटवारों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कोटवारों ने नियमित शासकीय कर्मचारी का दर्जा, पारिश्रमिक में वृद्धि, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता,बेगारी पर रोक तथा शिकायतों की निष्पक्ष जांच जैसी प्रमुख मांगें रखीं।

ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश के कोटवार वर्षों से शासन-प्रशासन और ग्रामीण जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। अल्प पारिश्रमिक में परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो गया है। लंबे समय तक सेवा देने के बाद भी पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलने से कोटवारों का भविष्य असुरक्षित बना हुआ है। एसोसिएशन ने महंगाई को देखते हुए वर्तमान पारिश्रमिक में वृद्धि की मांग करते हुए कहा कि सेवा भूमि नहीं रखने वाले कोटवारों का मानदेय 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये तथा अन्य श्रेणियों के मानदेय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की जाए। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि कोटवारों की नियुक्ति में परिवार के पात्र सदस्यों को प्राथमिकता देने के प्रावधान के बावजूद कई स्थानों पर अनियमितताएं हो रही हैं। एसोसिएशन ने नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा कोटवारों से उनके मूल दायित्वों के अतिरिक्त अन्य कार्य कराए जाने पर रोक लगाने, बिना निष्पक्ष जांच किसी भी कोटवार के विरुद्ध निलंबन या पदमुक्ति जैसी कार्रवाई नहीं करने तथा नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्रों में कोटवारों की नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग भी की गई। कोटवार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेते हुए आवश्यक शासनादेश जारी करने का आग्रह किया है।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं राजो बाई पति खसक उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम बकनाकला तह0 लुण्ड्रा जिला सरगुजा छ0म0 का उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।

यह कि मेरे पुत्र अंजीत कुमार (ANJIT KUMAR) के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अजीत कुमार (AJIT KUMAR) दर्ज हो गया है, जो गलत है, जिसका आधार नम्बर 726052568836 है।

कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा दसवीं के अंकसूची में उसका नाम अंजीत कुमार (ANJIT KUMAR) दर्ज है जो सत्य एवं सही है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका सही नाम अंजीत कुमार (ANJIT KUMAR) दर्ज कराने हेतु स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत है।

शपथग्रहिता
राजो बाई

न्यायालय तहसीलदार ओड़गी जिला-सूरजपुर,छत्तीसगढ़

रा.प्र.क्र......../......./2025-26
दिनांक 01/07/2026

ईश्तहार

(ग्राम पंचायत टोमो में प्रकाशन हो)

एतद् द्वारा ग्राम टोमो निवासरत् आमजनों को सूचित किया जाता है, कि आवेदक/ आवेदिक प्रवीण कुशवाहा आ. जयनंद कुशवाहा निवासी ग्राम टोमो तहसील ओड़गी जिला सूरजपुर (छ.ग.) द्वारा अपने दादी कयाशो का मृत्यु दिनांक 01.02.2001 को ग्राम टोमो में मृत्यु हुआ है। मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं।

आप ग्राम जनों को यदि उक्त जन्म/मृत्यु के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही से किसी भी प्रकार की आपत्ति हो या उक्त जन्म/मृत्यु के संबंध में कार्यवाही होने से किसी भी प्रकार का हित प्रभावित होता हो तो वह अपना दावा आपत्ति दिनांक 15/07/ 2026 के पूर्व इस न्यायालय मे स्वयं या किसी अभिभावक सह उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर किसी भी प्रकार से विचार नही किया जावेगा व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी ।

आज दिनांक 01/07/2026 को मेरे हस्तक्षार एवं न्यायालय की सील मुद्रा से जारी ।

सील
तहसीलदार
ओडगी जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदिका श्रीमती गुंजा बाई उर्फ गुड्डी बाई पुत्री हीराधन, कंजलसा भुईयां उर्फ कंजान राम आ0 हीराधन, जाति भुईया, निवासी मणीपुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा अपने स्वामित्व की शीट नम्बर -10 मोहल्ला - दर्रीपारा, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 3836 रकबा 0.04 एकड़ में से 0.02 एकड़ भूमि को अनावेदक / केता श्रीमती संगीता देवी पत्नी विष्णु अग्रवाल, जाति भूमियां, निवासी कबीर वार्ड जोड़ा टावर के पास, दर्रीपारा अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ0ग0 के पास बिक्रय करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा, शपथ पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 13.07.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक 24.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील
नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

कार्यालय अधिक्षण अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) अम्बिकापुर ,मण्डल अम्बिकापुर (छ0ग0)

निविदा आमंत्रण तिथि -26.06.2026

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

01. निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये Log in करें https://eproc.cgstate.gov.in
02. संबंधित संभाग- स.क्रं. 01 से 06 अम्बिकापुर एवं स.क्रं. 07 जशपुर संभाग
03. स.क्रं. 01, 02 'स' वर्ग एवं ऊपर ठेकेदार स.क्रं. 03 से 07 'द' वर्ग एवं ऊपर ठेकेदार
04. ऑनलाईन निविदा डालने की अंतिम तिथि - 20.07.2026

सरल क्र.	एन.आई.टी.क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3	4
1	115	जिला सरगुजा के विकासखण्ड उदयपुर में ट्रांजिट हॉस्टल (शिक्षक आवास) 3 यूनिट का निर्माण कार्य विद्युतीकरण सहित (प्रथम आमंत्रण)	126.23
2	116	जिला सरगुजा के विकासखण्ड मैनपाट के नर्मदापुर में ट्रांजिट हॉस्टल (शिक्षक आवास) 3 यूनिट का निर्माण कार्य विद्युतीकरण सहित (प्रथम आमंत्रण)	126.23
3	117	सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के अंतर्गत स्टोर (हॉल) का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)	35.93
4	118	सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के विभिन्न भवनों के सीपेज मरम्मत का कार्य (वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट) (प्रथम आमंत्रण)	47.69
5	119	सैनिक स्कूल अम्बिकापुर जिला सरगुजा में बाहरी और आंतरिक पहुंच मार्ग में बी टी रिनीवल का कार्य (प्रथम आमंत्रण)	99.00
6	120	सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के अंतर्गत बाउण्ड्रीवाल का मरम्मत कार्य (प्रथम आमंत्रण)	12.78
7	121	जिला जशपुर में फायर स्टेशन भवन एवं गैरज निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)	96.86

जी0नं0 -262701829/4

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग
अम्बिकापुर,मण्डल अम्बिकापुर

CMYK

15 लाख का रपटा...अब सड़क के लिए जनता से चंदा!

एप्रोच रोड अधूरी छोड़ने से बरसात में ठप हुआ आवागमन, स्टोन डस्ट डालने के लिए ग्रामीण घर-घर जुटा रहे सहयोग राशि

'घटती-घटना' की खबरों, कलेक्टर के संज्ञान और निरीक्षण के बाद बना रपटा, लेकिन एप्रोच रोड अधूरी छोड़ने से फिर दलदल में बदला रास्ता

'विकास का नया मॉडल' सरकार बनाए पुल...जनता बनाए सड़क...और अधिकारी बना लें उपलब्धि की रिपोर्ट!

- सरकारी सड़क नहीं बनी...अब ग्रामीण खुद बनाएंगे रास्ता...
- रपटा बना,सड़क नहीं...अब चंदे से चलेगा विकास...

15 लाख खर्च,फिर भी दलदल में विकास...अब जनता ने संभाली जिम्मेदारी...

सरकार ने बनाया पुल,सड़क के लिए जनता से मांगा वक्त... अब ग्रामीण मांग रहे चंदा...

जब व्यवस्था हार गई...तब गांव ने उठाई फावड़ा और चंदे की थैली

रपटा तक पहुंचने को चंदा! विकास की यह कैसी तस्वीर?

पुल सरकारी,सड़क जनसहयोग से...गोबरी रपटा बना व्यवस्था की नाकामी का प्रतीक

जनता पूछ रही–कर भी दें, चंदा भी दें...फिर सरकार किसलिए?

घटती-घटना | कोरिया- सूरजपुर समाचार | अम्बिकापुर शुक्रवार 03 जुलाई 2026 | 5

15 लाख का रपटा... लेकिन जनता अब भी कीचड़ में!

यह पुल नहीं, औपचारिकता बनकर रह गया!

कलेक्टर निरीक्षण के बाद बना रपटा, एप्रोच रोड अधूरा

रपटा में 15 लाख खर्च...फिर भी पुल तक पहुंचना दूभर,एप्रोच रोड बनी सबसे बड़ी बाधा

रपटा बन गया,सड़क नहीं...बरसात में फिर ठप हुआ आवागमन...

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,03 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। 'गोबरी नदी पर अब सिर्फ रपटा नहीं बना है, बल्कि सरकारी व्यवस्था और जनता के भरोसे के बीच भी एक गहरी खाई बन गई है,फर्क सिर्फ इतना है कि उस खाई पर पुल बनाने के लिए भी अब ग्रामीणों को चंदा करना पड़ रहा है,गोबरी नदी पर लगभग 15 लाख रुपये की लागत से निर्मित स्थायी रपटा पुल एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है, यह चर्चा किसी नई उपलब्धि की नहीं, बल्कि अधूरे निर्माण और प्रशासनिक लापरवाही की है, जिस रपटा पुल को क्षेत्रवासियों की महीनो पुरानी समस्या का समाधान बताया गया था,वह आज भी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है,कारण वही पुराना है–रपटा के दोनों ओर लगभग 300-300 मीटर तक एप्रोच रोड का अधूरा निर्माण। लेकिन अब इस मामले में नया और बेहद चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है,प्रशासन और संबंधित विभाग से निराश ग्रामीणों ने स्वयं आगे आकर सड़क को चलने योग्य बनाने का निर्णय लिया है,गांव के लोग अब घर-घर जाकर चंदा एकत्रित कर रहे हैं ताकि स्टोन डस्ट, मुरुम अथवा अन्य आवश्यक सामग्री खरीदकर रपटा के दोनों ओर के दलदली मार्ग को उपयोग योग्य बनाया जा सके, ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकार और विभाग उनकी समस्या नहीं सुन रहे हैं तो उन्हें अपनी परेशानी का समाधान स्वयं करना पड़ेगा।

'घटती-घटना' की मुहिम के बाद हरकत में आया था प्रशासन

दैनिक 'घटती-घटना' ने पिछले कई महीनों से गोबरी नदी पर अधूरे रपटा निर्माण और वैकल्पिक मार्ग की समस्या को लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया,समाचारों में यह सवाल उठाया गया था कि यदि रपटा के दोनों ओर मजबूत संपर्क मार्ग नहीं बनाया गया तो लाखों रुपये खर्च होने के बाद भी निर्माण आम जनता के किसी काम का नहीं रहेगा,लगातार प्रकाशित खबरों के बाद जिला कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लिया,अधिकारियों को स्थल निरीक्षण के निर्देश दिए गए और निर्माण कार्य में तेजी आई, परिणामस्वरूप रपटा पुल का निर्माण पूरा कर दिया गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा–दोनों ओर मजबूत एप्रोच रोड–आज भी अधूरा छोड़ दिया गया।

पहली बारिश में खुल गई निर्माण की हकीकत

बरसात शुरू होते ही रपटा के दोनों ओर डाली गई कच्ची मिट्टी दलदल में बदल गई, सड़क पर न तो जीएसबी डाली गई, न डब्ल्यूएमएम और न ही स्टोन डस्ट का उपयोग किया गया, परिणाम यह हुआ कि पहली ही बारिश में सड़क पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गई, दोपहिया वाहन फिसल रहे हैं, चारपहिया वाहन मिट्टी में धंस रहे हैं और पैदल चलना भी जोखिम भरा हो गया है, कई ग्रामीणों ने बताया कि रपटा बनने के बावजूद वे पुराने वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने को मजबूर हैं क्योंकि पुल तक पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।

अब जनता खुद बनाएगी रास्ता

ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जनप्रतिनिधियों ने भी मांग उठाई,लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई,अब लोगों ने स्वयं पहल करने का निर्णय लिया है,गांव-गांव और घर-घर जाकर चंदा एकत्रित किया जा रहा है ताकि स्टोन डस्ट या अन्य मिश्रण डालकर कम से कम बरसात के मौसम में रास्ते को चलने योग्य बनाया जा सके,ग्रामीणों का कहना है कि यह चंदा किसी विकास कार्य के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन को बचाने के लिए किया जा रहा है,बच्चों को स्कूल जाना है, किसानों को खेतों तक पहुंचना है,मरीजों को अस्पताल ले जाना है और महिलाओं को बाजार तक आना-जाना है, ऐसे में यदि सरकार सड़क नहीं बनाएगी तो जनता स्वयं अपनी राह बनाएगी।

यह केवल सड़क नहीं,व्यवस्था पर सवाल है...

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य तकनीकी रूप से पूरा नहीं था तो उसे पूर्ण कैसे घोषित कर दिया गया? यदि एप्रोच रोड तैयार नहीं थी तो भुगतान किस आधार पर किया गया? क्या गुणवत्ता परीक्षण हुआ था? क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी ने मौके पर जाकर देखा कि पहली बारिश में सड़क की क्या स्थिति होगी? लोगों का कहना है कि पुल का निर्माण कर फोटो खिंचवा लेना आसान है,लेकिन उसे वास्तव में उपयोगी बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

जनप्रतिनिधि ने भी उठाई थी मांग...

जनपद पंचायत भैयाथान सदस्य एवं सहकारिता एवं उद्योग विकास समिति के सभापति राजकुमार गुप्ता ने भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोनों ओर मजबूत एप्रोच रोड निर्माण की मांग की थी,उन्होंने कहा था कि किसान, छात्र, महिलाएं और आम नागरिक प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं तथा बरसात के दौरान यह समस्या और गंभीर हो जाएगी,इसके बावजूद आज तक स्थायी समाधान सामने नहीं आ सका।

15 लाख का रपटा...लेकिन जनता अब भी कीचड़ में!

गोबरी नदी पर बना पुल बना 'शोपीस', एप्रोच रोड गायब... सेतु विभाग और PWD की 'फुटबॉल' में पिस रही जनता

29 पुराने ह्यूम पाइप लगाने का आरोप,आठ महीने बाद भी आवागमन बाधित,सीएम हेल्पलाइन तक पहुंची शिकायतें,सवाल–क्या सरकारी निर्माण सिर्फ बिल पास कराने के लिए होते हैं?

3.60 करोड़ के पुल में तेजी...15 लाख का रपटा अब भी अधूरा-गोबरी नदी पर विकास की दो रफ्तार

ग्रामीणों का सवाल-जब सड़क हमें ही बनानी थी...तो 15 लाख रुपये किसलिए खर्च हुए?

ग्रामीणों का कहना है कि यदि आज भी उन्हें चंदा करके सड़क बनानी पड़ रही है तो फिर लाखों रुपये की सरकारी परियोजना का वास्तविक लाभ क्या हुआ? क्या सरकारी धन केवल रपटा तक सीमित था? क्या संपर्क मार्ग परियोजना का हिस्सा नहीं था? यदि था तो वह अधूरा क्यों छोड़ दिया गया? लोगों का कहना है कि सरकार का काम जनता से चंदा लेकर सड़क बनवाना नहीं,बल्कि करदाताओं के पैसे से गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराना है।

'घटती-घटना' के बड़े सवाल

- जब एप्रोच रोड तैयार नहीं थी तो निर्माण कार्य पूर्ण कैसे माना गया?
- क्या बिना जीएसबी,डब्ल्यूएमएम और स्टोन डस्ट के सड़क तकनीकी रूप से उपयोग योग्य मानी जा सकती है?
- क्या कार्य का गुणवत्ता परीक्षण और भौतिक सत्यापन किया गया था?
- पहली ही बारिश में सड़क दलदल में बदल गई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
- यदि ग्रामीण स्वयं चंदा जुटाकर सड़क बनाएंगे तो संबंधित विभाग की भूमिका क्या रह जाएगी?
- क्या निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी?

अब प्रशासन की परीक्षा

गोबरी नदी पर बना रपटा निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों के लिए राहत का माध्यम बन सकता है,लेकिन तभी जब उससे जुड़ा संपर्क मार्ग भी मजबूत और हर मौसम में उपयोग योग्य बनाया जाए, वर्तमान स्थिति में पुल तो बन गया है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता ही दलदल में बदल चुका है,इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि अब ग्रामीणों ने प्रशासन से उम्मीद छोड़कर खुद चंदा इकट्ठा कर सड़क सुधारने का निर्णय ले लिया है,यह केवल एक सड़क का मामला नहीं है,बल्कि उस व्यवस्था पर बड़ा सवाल है, जिसमें जनता कर भी देती है,सरकार योजनाएं भी बनाती है, बजट भी खर्च होता है,लेकिन अंत में सड़क बनाने के लिए फिर जनता को ही अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है,अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस जनसहयोग को अपनी विफलता मानेगा या फिर समय रहते अधूरी परियोजना को वास्तव में पूर्ण कर जनता को राहत देगा।

किसान क्या करें, जब बाड़ ही खेत खाने लगे!

कोरिया में प्रशासनिक 'सेटिंग' का ऐसा खेल, जहां नियम फाइलों में और प्रभार रिश्तों में तय होते हैं

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रकोष्ठ वानिकी
विभागीय कार्यालय, "इन्द्रावती भवन", द्वितीय खण्ड, अटल नगर रायपुर (छ.ग.)
☎ 0771-2433001, फैक्स : 0771-243002
E-mail : dir.horti-cg@nic.in, Website : http://agriportal.cg.nic.in/horticulture/HortiHi/

क्रमांक/उद्यान/स्था./आर.सं./2026/ 1329 नवा रायपुर, दिनांक 23/06/2026

– आदेश –

संचालनालयीन आदेश क्र./उद्यान/स्था.2/2026-27/322-23 दिनांक 23.04.2026 के द्वारा श्री ययपाल सिंह मरावी, सहायक संचालक उद्यान, जिला-सूरजपुर को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ सहायक संचालक उद्यान, जिला-कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का [illegible] प्रभार सौंपा गया था। [illegible] संशोधन करते हुए श्री विनय कुमार त्रिपाठी, सहायक संचालक उद्यान, जिला-कवर्धा को [illegible] कोरिया का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। श्री ययपाल सिंह मरावी, सहायक संचालक उद्यान, जिला-सूरजपुर अतिरिक्त प्रभार सहायक संचालक उद्यान, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का प्रभारी यथावत रहेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

23/06/26
(लोकेश कुमार)
भा.प्र.से.
संचालक
उद्यानिकी एवं प्रकोष्ठ वानिकी
छ.ग. रायपुर

आदेश जारी
23/06/2026

कोरिया में 'सेटिंग मॉडल' का कमाल,400 किमी दूर से आया अतिरिक्त प्रभार

योग्यता नहीं,जुगाड़ बना नियुक्ति का नया पैमाना?

नियम फाइलों में कैद,प्रभार पहुंचा 400 किलोमीटर दूर से... कोरिया में प्रशासनिक खेती: फसल जनता की...लाभ सेटिंग का!

जहां सेटिंग मजबूत...वहीं अतिरिक्त प्रभार की गारंटी! कोरिया में प्रतिभा का अकाल या फिर सेटिंग का कमाल?

जब व्यवस्था ही व्यवस्था को खाने लगे...तब जनता किससे उम्मीद करे?

प्रभार एक्सप्रेस : कवर्धा से कोरिया तक 400 किलोमीटर का प्रशासनिक सफर

प्रशासनिक नूरा-कुश्ती का नया अध्याय,जनता फिर बनी दर्शक

कोरिया में नियम नहीं,रिश्ते तय कर रहे हैं जिम्मेदारियां?

कोरिया में प्रशासनिक 'सेटिंग' का ऐसा खेल,जहां नियम फाइलों में और प्रभार रिश्तों में तय होते हैं?

रवि सिंह

कोरिया,03 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले में इन दिनों प्रशासनिक व्यवस्था किसी सरकारी कार्यालय से कम और शतरंज के ऐसे अखाड़े से ज्यादा दिखाई दे रही है, जहां मोहरे जनता नहीं, बल्कि अधिकारी चल रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि यहां शह-मात नियमों से नहीं,बल्कि 'सेटिंग' से होती है, कहावत है कि 'जब बाड़ ही खेत खाने लगे तो किसान किससे न्याय मांगे?' कोरिया जिले के हालात देखकर लगता है कि अब इस कहावत का संशोधित संस्करण तैयार करना पड़ेगा– 'जब चौकीदार ही चाबी बांटने लगे तो ताला लगाने का क्या फायदा?'

पहला अंक : दोस्ती,दूरी और दरबार

कहानी शुरू होती है एक ऐसे जिला अधिकारी से, जिनकी पहचान कभी जिले के तत्कालीन मुखिया के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार के रूप में होती थी, दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि फाइलें कम और तालमेल ज्यादा चलता था, लेकिन कहते हैं न, राजनीति हो या नौकरशाही, यहां स्थायी केवल स्वार्थ होता है, एक दिन ऐसा आया कि दोस्ती की मिठास में खटास घुल गई, फिर क्या था, तबादले की फाइल चली और साहब ने नया जिला चुन लिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।

दूसरा अंक : भारमुक्ति का महाभारत

तबादला हो गया, लेकिन भारमुक्ति नहीं हुई, मानो कार्यालय नहीं, पुश्तैनी जमीन का बंटवारा चल रहा हो, आखिरकार अधिकारी महोदय सीधे माननीय उच्च न्यायालय की शरण में पहुंचे, न्यायालय ने आदेश दिया कि भाई साहब को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए, फिर क्या था... साहब आदेश की प्रति लेकर ऐसे लौटे जैसे कोई योद्धा युद्ध जीतकर आया हो, कार्यालय पहुंचे, आदेश दिखाया, कार्यमुक्त हुए और छह महीने पहले मिले नए जिले में जाकर विधिवत आमद भी दे दी, जनता ने राहत की सांस ली कि चलिए, अब यह अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन जनता प्रशासन को अभी जानती कहां थी...

तीसरा अंक: मुखिया बदला, पटकथा वही रही-

इसी बीच जिले के मुखिया का भी तबादला हो गया, वही मुखिया, जिनके कार्यकाल में पुरस्कारों की बरसात होती रही, जिनके हर कार्यक्रम में उपलब्धियों के पुल बांधे गए, लेकिन यदि उन्हीं उपलब्धियों और उनके कार्यकाल की भर्तियों की निष्पक्ष जांच हो जाए तो शायद कई पुरस्कारों की चमक फीकी पड़ जाए, आज भी कई मामले ऐसे हैं, जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप सत्यापन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फाइलें 'सुलहनामा' और 'विचाराधीन' की नींद सो रही हैं।

चौथा अंक: सेटिंग एक्सप्रेस, 400 किलोमीटर नॉन-स्टॉप-

अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है, जिले में नई फील्डिंग सजाई गई, चर्चाओं के अनुसार, जिले के एक प्रभावशाली अधिकारी और कोयला चोरी की चर्चाओं में रहने वाले एक युवा नेता की सक्रियता के बीच ऐसा समीकरण बना कि प्रशासन ने प्रतिभा की खोज सीधे कवर्धा में जाकर पूरी की, और देखते ही देखते लगभग 400 किलोमीटर दूर बैठे अधिकारी को कोरिया जिले का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया, आदेश जारी हुआ...साहब आए... सीधे कुर्सी संभाली...और जनता सोचती रह गई– 'क्या कोरिया में अधिकारी विलुप्त प्रजाति घोषित हो चुके हैं?' 23 जून 2026 के आदेश के अनुसार कवर्धा के सहायक संचालक उद्यान विनय कुमार त्रिपाठी को कोरिया जिले का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

प्रतिभा खोज प्रतियोगिता सिर्फ कोरिया के लिए?– अब कुछ भोले-भाले सवाल हैं क्या पूरे सरगुजा संभाग में कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं था? क्या सूरजपुर,बलरामपुर,एमसीबी या सरगुजा में योग्य अधिकारी समाप्त हो गए? या फिर प्रतिभा की असली खान केवल 400 किलोमीटर दूर ही मिली? यदि यही व्यवस्था है तो फिर अगले आदेश में दिल्ली, भोपाल या जयपुर से भी किसी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देकर देख लिया जाए, प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती।

कोरिया का नया प्रशासनिक फार्मूला– यहां योग्यता का गणित बड़ा सरल है–

- योग्यता + सेटिंग = अतिरिक्त प्रभार
- दूरी ‸ नियम = प्रशासनिक सुविधा
- जनहित - पारदर्शिता = व्यवस्था सफल

किसान तो बस तमाशा देख रहा है– उधर किसान खेत में खड़ा सोच रहा है– खाद महंगी...बीज महंगा...सिंचाई अधूरी...योजनाएं फाइलों में... और जिन अधिकारियों से उम्मीद थी कि वे व्यवस्था संभालेंगे, वे खुद अतिरिक्त प्रभार, तबादलों और समीकरणों की खेती में व्यस्त हैं, किसान को अब समझ नहीं आ रहा कि फसल बचाए या व्यवस्था।

अंतिम व्यंग्य...कोरिया जिले की जनता को अब गर्व होना चाहिए...

यह जिला शायद देश का पहला ऐसा जिला बनता जा रहा है जहां अधिकारी स्थानीय नहीं, 'आयातित' मिलते हैं,निर्णय प्रशासनिक कम और राजनीतिक ज्यादा दिखाई देते हैं, नियम पुस्तकों में रहते हैं और व्यवस्थाएं फोन पर तय होती हैं, फिलहाल जनता निश्चिंत रहे...कोरिया को एक और 'अत्यंत प्रतिभाशाली' अतिरिक्त अधिकारी मिल गया है, अब देखना केवल इतना है कि इस अतिरिक्त प्रतिभा से जिले का उद्यान विकसित होगा या फिर केवल 'सेटिंग का बगीचा' और हरा-भरा होगा।

व्यंग्य का पंच

'कोरिया में अब अधिकारी नहीं भेजे जाते, 'प्रभार' भेजा जाता है...और प्रभार भी वहीं जाता है,जहां सेटिंग का पौधा सबसे हरा दिखाई देता है। '

कोटा में राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं : शशि सिंह

जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा– युवाओं के अधिकारों की लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ, शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग दोहराई

-संवाददाता-

सूरजपुर,03 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। जिला कांग्रेस कमेटी सूरजपुर के मीडिया विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह ने राजस्थान के कोटा में आयोजित नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी के छात्रों की गूंज महा-संवाद कार्यक्रम को युवाओं की आवाज़ बुलंद करने वाला आयोजन बताया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देशभर से पहुंचे प्रतियोगी छात्रों से संवाद करते हुए नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा तथा छात्रों के भविष्य की रक्षा का भरोसा दिलाया। विज्ञप्ति के अनुसार राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं से देश के लाखों मेहनती छात्रों और उनके परिवारों के सपनों पर आघात पहुंचा है,उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार विफल रही है, राहुल गांधी ने छात्रों से कहा कि वे स्वयं को अकेला न समझें और उनकी आवाज़ संसद से लेकर सड़क तक उठाई जाएगी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह ने कहा कि देश के अनेक छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, ऐसे में यदि परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं तो इसका सबसे अधिक नुकसान ईमानदारी से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी, शशि सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी दोहराई, उनका कहना था कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए जवाबदेही तय होना आवश्यक है,उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस मामले में संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है,विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि जिला कांग्रेस कमेटी सूरजपुर राहुल गांधी के आह्वान के अनुरूप युवाओं और छात्रों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर आगे भी आवाज़ उठाती रहेगी। कांग्रेस का दावा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित कराने के लिए पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी।

9 दिन का आंदोलन,6 माह का इंतजार...फिर भी अंधेरे में 17 गांव

ठंड में मिला था बिजली का आश्वासन,गर्मी गुजर गई,अब बरसात भी शुरू...लेकिन आज भी नहीं पहुंची बिजली

महुली से नवडीहा तक लाइन विस्तार का था वादा,वनांचल के अन्य गांवों में सौर ऊर्जा व्यवस्था भी पूरी तरह ठप्प... 12 हजार से अधिक ग्रामीण परेशान

ओंकार पाण्डेय

सूरजपुर,03 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। सूरजपुर जिले के दूरस्थ वनांचल चांदनी-बिहरपुर क्षेत्र के 17 गांव आज भी बिजली की रोशनी का इंतजार कर रहे हैं, करीब छह माह पहले कड़ाके की ठंड में बिजली की मांग को लेकर बिहरपुर तहसील मैदान में नौ दिनों तक चले आंदोलन के बाद जिला प्रशासन ने जल्द विद्युत लाइन विस्तार और सौर ऊर्जा व्यवस्था बहाल करने का भरोसा दिया था,लेकिन ठंड बीत गई,भीषण गर्मी निकल गई और अब बरसात का मौसम भी शुरू हो चुका है,फिर भी न बिजली के खंभे लगे,न तार खिंचे और न ही बंद पड़ी सौर ऊर्जा व्यवस्था को चालू किया जा सका, ग्रामीणों का कहना है कि आंदोलन के दौरान प्रशासन ने महुली,कोल्हूआ,कछवारी, खैरा, चोगा,कछिया और नवडीहा तक विद्युत लाइन विस्तार कराने का आश्वासन दिया था, वहीं इन गांवों से आगे स्थित दुर्गम पहाड़ी और वन क्षेत्रों में क्रेडा के माध्यम से सौर ऊर्जा आधारित बिजली व्यवस्था विकसित करने की बात कही गई थी। लेकिन छह माह बीत जाने के बाद भी दोनों योजनाएं केवल कागजों तक सीमित दिखाई दे रही हैं।

करीब 12 हजार ग्रामीण अब भी अंधेरे में–चांदनी-बिहरपुर क्षेत्र के इन 17 गांवों में लगभग 12 हजार से अधिक ग्रामीण निवास करते हैं, बिजली नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, मरीजों को रात में इलाज कराने में दिक्कत होती है,मोबाइल चार्ज करना भी चुनौती बना हुआ है और घरेलू कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं,बरसात शुरू होने के बाद अंधेरे में जहरीले सांप-बिच्छू और जंगली जानवरों का खतरा बढ़ गया है,जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है।

कड़ाके की ठंड में नौ दिन तक चला था आंदोलन–ग्रामीणों के अनुसार बिजली की मांग को लेकर सैकड़ों महिला-पुरुष,बुजुर्ग और युवा लगातार नौ दिनों तक बिहरपुर तहसील मैदान में धरने पर बैठे रहे, भीषण ठंड के बावजूद आंदोलन जारी रहा। इस दौरान कई आंदोलनकारियों की तबीयत बिगड़ी,वहीं कुछ ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप मुंडन कराकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया,आंदोलन के नौवें दिन प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शीघ्र कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया,जिसके बाद आंदोलन समाप्त किया गया।

दो वर्षों से बंद पड़े हैं सोलर प्लांट–ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में क्रेडा द्वारा वर्षों पहले स्थापित दो दर्जन से अधिक सोलर पावर प्लांट, होम लाइट सिस्टम और इनवर्टर पिछले लगभग दो वर्षों से बंद पड़े हैं,अधिकांश बैटरियां खराब हो चुकी हैं, इनवर्टर जवाब दे चुके हैं और रखरखाव के अभाव में पूरी व्यवस्था निष्क्रिय हो गई है, कई गांवों में सोलर प्लांट केवल लोहे के ढांचे बनकर रह गए हैं,जबकि ग्रामीण मजबूरी में फिर लालटेन और अन्य पारंपरिक साधनों का सहारा ले रहे हैं।

'प्रक्रिया जारी है' का जवाब, लेकिन काम शुरू नहीं–ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली जाती है तो केवल 'प्रक्रिया जारी है' कहकर मामला टाल दिया जाता है, छह माह बाद भी न लाइन विस्तार का कार्य प्रारंभ हुआ और न ही सौर ऊर्जा व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की दिशा में कोई ठोस पहल दिखाई दे रही है,इससे लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है।

बरसात में बढ़ी चिंता,फिर आंदोलन की चेतावनी– ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और राज्य शासन से मांग की है कि आंदोलन के दौरान किए गए वादे को तत्काल पूरा किया जाए, महुली, कोल्हूआ, कछवारी, खैरा,चोगा, कछिया और नवडीहा तक विद्युत लाइन विस्तार का कार्य बिना और विलंब के शुरू कराया जाए, साथ ही वनांचल के अन्य गांवों में नई सौर ऊर्जा व्यवस्था स्थापित कर वर्षों से बंद पड़े सोलर पावर प्लांट,होम लाइट और इनवर्टर की मरम्मत अथवा प्रतिस्थापन कराया जाए, ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र ही कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो वे एक बार फिर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को विवश होंगे,उनका कहना है कि छह माह पहले मिला आश्वासन आज भी अधूरा है और 17 गांवों के हजारों लोग अब भी बिजली की रोशनी का इंतजार कर रहे हैं।

निर्माणाधीन शासकीय पॉलिटेक्निक भवन का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण

निर्माण कार्य की धीमी गति पर जताई नाराजगी,पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश

-संवाददाता-

सूरजपुर,03 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। जिले में शिक्षा अधोसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से निर्माणाधीन शासकीय पॉलिटेक्निक भवन का गुरुवार को कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने औचक निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता और कार्य की गति का जायजा लिया। निर्माण कार्य अपेक्षित गति से नहीं होने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर भवन का निर्माण पूर्ण किया जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने

निर्माण स्थल का बारीकी से अवलोकन किया तथा विभिन्न हिस्सों में चल रहे कार्यों की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की,उन्होंने निर्माण कार्य की वर्तमान प्रगति, उपयोग में लाई जा रही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता तथा शेष कार्यों को पूरा करने की कार्ययोजना के संबंध में विस्तार से जानकारी ली,उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भवन निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा, सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से किए जाएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या उत्पन्न न हो,कलेक्टर रेना जमील ने कहा कि शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थान जिले के युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण केंद्र है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए भवन के तैयार होने से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, पर्याप्त कक्षाएं, प्रयोगशालाएं तथा अन्य आवश्यक अधोसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध होंगी,उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य की नियमित निगरानी की जाए और निर्माण एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित कर शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कराया जाए, उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा,यदि किसी स्तर पर लापरवाही या कार्य में अनावश्यक विलंब पाया गया तो संबंधित अधिकारियों और एजेंसी की जवाबदेही तय की जाएगी,साथ ही उन्होंने निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों का भी विशेष रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता ललित भोई ने भवन निर्माण की प्रगति एवं शेष कार्यों की जानकारी कलेक्टर को दी, वहीं एसडीओ एस.के. मिश्रा ने निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना से अवगत कराया, शासकीय पॉलिटेक्निक सूरजपुर के प्रभारी प्राचार्य विवेक कुमार मेहता भी निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे और उन्होंने नए भवन के निर्माण पूर्ण होने से विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी, कलेक्टर के औचक निरीक्षण के बाद निर्माण एजेंसी एवं संबंधित अधिकारियों में भी कार्य में तेजी लाने की गंभीरता दिखाई दी, प्रशासन का स्पष्ट उद्देश्य है कि निर्माणाधीन शासकीय पॉलिटेक्निक भवन का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कर विद्यार्थियों को जल्द से जल्द आधुनिक संसाधनों और बेहतर शैक्षणिक वातावरण से युक्त नया परिसर उपलब्ध कराया जा सके, इससे जिले में तकनीकी शिक्षा को नई गति मिलने के साथ युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुविधाओं का लाभ भी प्राप्त होगा।

चाय की चुस्कियों के साथ शूट हुआ था यह रोमांटिक सॉन्ग, जुबान पर एक बार चढ़ जाए तो नहीं उतरता स्वाद

साल 1974 में राजेश खन्ना और जीनत अमान का एक रोमांटिक गाना आया था जिसने ऑनलाइन हलचल मचा दी थी। इस गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी।

बॉलीवुड ने हमें हर एक मूड के लिए गानें दिए हैं। इसमें प्यार है,रोमांस है, तकरार है, लड़ाई-शिकायत सबकुछ भरा हुआ है। लेकिन अगर संगीत को एक जायके की तरह महसूस किया जाए तो बरसात के गानों का अलग ही आलम होता है।

ये सीधा आपके दिल और दिमाग पर असर करते हैं। बरसात के गानों में कुछ अलग ही स्वाद मिलता है। आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे ही गाने के बारे में बताने वाले हैं जिसे हिंदी सिनेमा के इतिहास में रोमांटिक और सेंशुअल गानों का एक ऐसा मील का पत्थर है, जिसने हर तरह के श्रोताओं को अपना दीवाना बनाया।

किशोर कुमार ने दी थी आवाज

हम बात कर रहे हैं साल 1974 में आई फिल्म अजनबी के गाने भीगी भीगी रातों में के बारे में। इसे लीजेंड्री सिंगर किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। इस खूबसूरत गाने का संगीत आर. डी. बर्मन ने दिया जबकि इसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे।

इस गाने के बोल ऐसा लगता है, तुम बन के बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो उस दौर के सबसे रोमांटिक और चुलबुले बोल माने जाते थे। आनंद बख्शी ने बारिश की बूंदों और प्रेमी-प्रेमिका की छेड़छाड़ को जिस तरह से शब्दों में पिरोया, उसने इस गाने को अमर बना दिया।

ठंड से बचने के लिए निकाला ये तरीका

भीगी भीगी रातों में को आर्टिफिशियल बारिश में शूट किया गया था। इस आर्टिफिशियल बारिश के लिए जो स्प्रिंकलर लगाए गए थे वो बार-बार रुक जाते थे ऐसे में एक्टर्स को इतनी ठंड लगने लगती थी कि वो खुद को गर्म रखने के लिए रीटेक के बीच लगातार चाय की चुस्कियां लेते रहे थे।

कैसे निकाली बादल गरजने की आवाज

गाने में राजेश खन्ना और जीनत अमान की बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली। इस गाने के बारे में एक और दिलचस्प बात ये है कि इसकी शुरुआत में जो बाद गरजने की आवाज सुनाई देती है उसे किसी मशीन से नहीं निकाला गया। आर.डी. बर्मन ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एस्बेस्टस की एक बड़ी चादर को हिलाकर और टकराकर उस गर्जना का प्रभाव पैदा किया था जोकि गाने में सुनने में एकदम असली लगता है।

ये राजेश खन्ना और अभिनेत्री जीनत अमान के करियर की पहली फिल्म थी, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर की थी। इस गाने का साल 2000 में एक रीमेक भी बना था जिसे अदनान सामी ने गाया था।

आलिया भट्ट की अल्फा ने एडवांस बुकिंग में मचाया धमाल,रिलीज से पहले करोड़ छापे?

वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की पहल फीमेल लीड फिल्म अल्फा साल की मच अवेटेड फिल्म है और ये इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। वहीं आलिया भट्ट स्टारर इस स्पाई-एक्शन फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और प्री टिकट सेल के शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि थिएटर में रिलीज से पहले ही इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अल्फा ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में कितनी कमाई कर डाली है?

अल्फा की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है और इसी के साथ फिल्म की खूब प्री टिकट सेल हो रही है। सैकनिल्क के शुरुआती एडवांस बुकिंग आंकड़ों के मुताबिक अल्फा ने भारत में 10 हजार 293 हिंदी (2डी) शो के जरिए अपने पहले दिन के लिए 41.06 करोड़ कमा लिए हैं। वहीं ब्लॉक की गई सीटों को मिलाकर, फिल्म की पहले दिन की एडवांस बुकिंग की कमाई फिलहाल 1.52 करोड़ है।

बता दें कि इस फिल्म को प्री टिकट सेल में महाराष्ट्र से सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहां ब्लॉक की गई सीटों सहित इसने 34.76 लाख की एडवांस बुकिंग की है। इसके बाद दिल्ली का नंबर है,जहां इस फिल्म ने 34.35 लाख की बुकिंग की है जबकि गुजरात ने फिल्म की रिलीज से पहले की कमाई में 10.66 लाख का कॉन्ट्रिब्यूशन दिया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मौजूदा ट्रेंड्स और शुरुआती अनुमानों के आधार पर,अल्फा के भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 7 से 8 करोड़ (नेट) की कमाई करने की उम्मीद है। हालांकि ये आंकड़े किसी फ्रैंचाइजी फिल्म के लिए खास ओपनिंग नहीं है,लेकिन अभी भी स्पॉट बुकिंग (मौके पर टिकट खरीदने) की गुंजाइश है। वहीं अगर इसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो इसके पहले दिन के कलेक्शन में इजाफे की उम्मीद है. देखने वाली बात होगी कि क्या ये डबल डिजिट में ओपनिंग कर पाएगी या नहीं? अल्फा वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली ऐसी एक्शन फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में कोई महिला है। पिछले कुछ सालों में,यह सिनेमैटिक यूनिवर्स एक था टाइगर,टाइगर ज़िंदा है,वॉर और पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ आगे बढ़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म कर पाती है।

जन नायकन को सीबीएफसी से मिली मंजूरी!

जल्द सिनेमाघरों में दस्तक देगी विजय की आखिरी फिल्म

तमिलनाडु के सीएम विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले इसे 9 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था,हालांकि इसकी रिलीज डेट सीबीएफसी सर्टिफिकेशन इश्यू की वजह से टलती रही थी लेकिन अब फैंस के लिए गुड न्यूज है। दरअसल खबरें हैं कि ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. चलिए जानते हैं ये कब थिएटर में दस्तक देगी? रिपोर्ट के मुताबिक,जना नायकन को ए सर्टिफिकेट मिल गया है,जिससे इसकी अब इसकी रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले,फिल्म के सर्टिफेकेशन प्रोसेस में मुश्किलें आ गई थीं क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने मंजूरी देने के बजाय दोबारा जांच की मांग की थी। इसके बाद प्रोडक्शन हाउस ने सीबीएफसी के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी,लेकिन बाद में केस वापस ले लिया और रिव्यू प्रोसेस का रास्ता चुना। वहीं सेंसर से मंजूरी मिलने की खबर के बाद,इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि मेकर्स जल्द ही फिल्म की थिएटर रिलीज की अनाउंसमेंट कर सकते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक एच विनोथ के निर्देशन में बनी यह फिल्म जुलाई 2026 में रिलीज हो सकती है। खबरों के मुताबिक,जन नायकन के प्रोड्यूसर्स अभी 16 जुलाई को फिल्म रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि, अगर यह तारीख मुमकिन नहीं हुई, तो 23 जुलाई पर भी विचार किया जा रहा है। विजय की इस फिल्म के लिए 31 जुलाई की तारीख भी एक ऑप्शन हो सकती है,लेकिन इस पर अभी पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसी दिन उनके बेटे जेसन संजय की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म सिग्मा भी रिलीज हो रही है।

वहीं अगर जुलाई में रिलीज मुमकिन नहीं हुई,तो जना नायकन के मेकर्स 7 अगस्त का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि ये स्लॉट खाली है। यानी इस दिन कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। हालांकि जन नायकन की रिलीज डेट के बारे में प्रोड्यूसर्स की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जन नायकन का बजट 350 करोड़ से 380 करोड़ के बीच बताया जा रहा है।. यानी थलपति विजय की ये काफी मोटी लागत में बनी है। वहीं ये तमिल की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक बताई जा रही है. गौरतलब है कि इस फिल्म से थलपति विजय की फीस ही 220 से 250 करोड़ के करीब बताई जा रही है। जन नायकन विजय के करियर का एक अहम प्रोजेक्ट है और यह उनकी आखिरी फिल्म भी है,क्योंकि इसके बाद वे पूरी तरह से राजनीति में उतर गए। एच. विनोथ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पूजा हेगड़े मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में हैं। वहीं सपोर्टिंग कलाकारों में बॉबी देओल, गौतम वासुदेव मेनन,प्रकाश राज,प्रियामणि, ममिता बैजू,नारायण और कई अन्य शामिल हैं। इसका म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है।

एवनग्रीन गीत की आज भी है खास पहचान

भारतीय संगीत जगत के दिग्गज गायक मोहम्मद रफी अपनी सुरीली आवाज और बहुआयामी गायकी के लिए आज भी याद किए जाते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा को ऐसे अनगिनत सदाबहार गीत दिए, जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। लता मंगेशकर सहित उस दौर के कई बड़े गायकों और संगीतकारों के साथ उनका काम भारतीय फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग का हिस्सा माना जाता है। मोहम्मद रफी की आवाज में वह खास जादू था, जो हर तरह के गीतों में ढल जाती थी–चाहे वह रोमांटिक गाना हो,भक्ति गीत,सूफी संगीत या फिर देशभक्ति गीत। उनकी गायकी की यही विविधता उन्हें अपने समय के सबसे अलग और सम्मानित गायकों में शामिल करती है। हालांकि, उनकी सफलता की यह यात्रा हमेशा आसान नहीं रही। अपने करियर के शुरुआती और मध्य दौर में उन्हें कई तरह की आलोचनाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब कुछ लोगों ने उन्हें गायकी छोड़ने तक की सलाह दे दी थी। यह वह दौर था जब संगीत इंडस्ट्री में नए कलाकारों का उभार हो रहा था और प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके बावजूद मोहम्मद रफी ने अपने हुनर और मेहनत पर भरोसा बनाए रखा। उन्होंने आलोचनाओं को अपने काम पर असर नहीं डालने दिया और लगातार अपनी गायकी को निखारते रहे। यही कारण है कि उन्होंने समय के साथ खुद को साबित किया और भारतीय फिल्म संगीत में एक अमिट पहचान बनाई। उनकी आवाज केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रही, बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ गई। चाहे प्रेम गीत हो या दर्द भरे नगमे, रफी साहब ने हर गीत में अपनी आत्मा डाल दी। यही वजह है कि उनके गाए गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उस दौर में थे। संगीतकारों और फिल्म निर्माताओं के बीच भी उनकी काफी मांग थी। वे हर गीत को पूरी गंभीरता और समर्पण के साथ गाते थे। कहा जाता है कि वे गीत के भाव और स्थिति को समझकर अपनी आवाज में वैसा ही असर पैदा करते थे, जिससे गीत जीवंत हो उठता था। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि प्रतिभा और मेहनत के दम पर किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। आलोचनाओं और संघर्षों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अंततः भारतीय संगीत के सबसे सम्मानित गायकों में स्थान बनाया। आज भी मोहम्मद रफी के गाने नए और पुराने सभी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। उनकी आवाज समय की सीमाओं से परे जाकर लोगों के दिलों में बस गई है।

अक्षय की फिल्म से एग्जिट के बाद प्रियदर्शन का बयान,बोले...मेरी बेइज्जती की

अक्षय कुमार की हेरी-फेरी 3 से एग्जिट लेने के बाद प्रियदर्शन ने अब कहा कि वे इसे धुरंधर से बड़ी फ्रैंचाइजी बनाने वाले थे। प्रियदर्शन ने हेरा फेरी 3 से जुड़ी पर्दे के पीछे की उथल-पुथल के बारे में खुलकर बात की है और उनके बयानों से इस पसंदीदा फ्रैंचाइजी के लिए हालात काफी निराशाजनक लग रहे हैं। एक खास बातचीत में, फिल्ममेकर ने क्रिएटिव मतभेदों और चल रहे विवादों, दोनों पर खुलकर अपनी बात रखी।

प्रियदर्शन ने हेरी-फेरी 3 से एग्जिट पर की बात

हेरी-फेरी 3 से एग्जिट लेने पर साफ-साफ बात करते हुए प्रियदर्शन ने कहा, फिरोज ने अक्षय से कहा था, तुम्हारे पास हेरा फेरी 3 बनाने के अधिकार हैं, लेकिन इसे कभी भी प्रियदर्शन के साथ मत बनाना। बस यही मेरी गुजारिश है। उन्होंने कई बार मेरी बेइज्जती की है,उन्होंने मुझसे कहा था कि हेरा फेरी का मेरा कट किसी गरीब आदमी के वर्शन जैसा लगता था,और उन्हें मेरी पांच घंटे की फिल्म को एडिट करना पड़ा था। डायरेक्टर ने माना कि पहले हुए इन मतभेदों के बावजूद,फ्रैंचाइजी की संभावना को देखते हुए वह शुरू में तीसरे पार्ट के लिए तैयार हो गए थे।

धुरंधर से भी बड़ी बनाता- प्रियदर्शन

उन्होंने बताया, शुरू में मैं अक्षय के साथ तीसरा पार्ट बनाने के लिए तैयार हो गया था क्योंकि मुझे लगा कि मैं देश की सबसे बड़ी फ्रैचाइजी में से एक बना सकता हूं। अगर मैंने इसे डायरेक्ट किया होता,तो मैं इसे धुरंधर से भी बड़ा बना सकता था। अक्षय कुमार , सुनील शेट्टी और परेश रावल ने मुझसे हेरा फेरी 3 बनाने का अनुरोध किया था। जब मैंने उन्हें कहानी सुनाई, तो वे सभी बहुत उत्साहित थे।

फ्रैंचाइजी के फ्यूचर पर जताई चिंता

फिल्ममेकर ने फिल्म के फ्यूचर पर चिंता जताते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा था कि तीसरी किस्त शायद उन्हीं कलाकारों के साथ रिलीज ना हो पाए क्योंकि इसमें बहुत सारे कानूनी मामले हैं। मेरे हिसाब से,हेरा फेरी (2000) का जन्म हुआ,हेरा फेरी 2 (2006) बीमार पड़ गई, और हेरा फेरी 3 खत्म हो जाएगी।

हेरा फेरी 3 को लेकर लंबे वक्त से गहमा गहमी बनी हुई है। पहले कानूनी मामले,फिर परेश रावल का बाहर और फिर फिल्म में एंट्री होना। इसके बाद प्रियदर्शन का फिल्म से एग्जिट लेना। फिलहाल फिल्म की शूटिंग और इसके बनने के बारे में कोई बड़ा अपडेट नहीं है लेकिन इतना कंफर्म है कि यह फिल्म बन रही है।

खेल समाचार

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड ने किया टीम का ऐलान

14 जुलाई से भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे श्रंखला भी खेली जाने वाली है...

नई दिल्ली,03 जुलाई 2026। भारत और इंग्लैंड के बीच मैजूदा समय में 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। इसके बाद 14 जुलाई से 3 मैचों की वनडे श्रंखला भी खेली जाने वाली है। बीसीसीआई की ओर से 21 जून को ही टीम का ऐलान कर दिया गया था। वहीं आज यानि 3 जुलाई को मेजबानों ने भी 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। जिसकी कमान हैरी ब्रूक संभालने वाले हैं।

इंग्लैंड ने किया 16 सदस्यीय टीम का ऐलान

इंग्लैंड ने वनडे सीरीज के लिए टीम की कमान 27 वर्षीय हैरी ब्रूक को सौंपी है। पिछले साल उन्हें पहली बार यह जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा ससेक्स की ओर से खेलने वाले ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को पहली बार वनडे टीम में जगह मिली है। जॉश टंग के पास भी 50 ओवर के खेल में पदार्पण करने का मौका है। इंग्लैंड के लिए उन्होंने 12 टेस्ट मैचों में 57 विकेट लिए हैं।

इंग्लैंड की टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल रशीद, जो रूट और जोश टंग।

भारत ने 21 जून को किया था टीम का ऐलान

बीसीसीआई की ओर से 21 जून को वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया था। विराट कोहली का खेलना फिटनेस पर निर्भर करता है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप 2023 फाइनल के बाद पहली बार एकदिवसीय फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। नीतीश कुमार रेड्डी का चयन भी हुआ था लेकिन वे अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में चोटिल हो गए थे।

भारत की टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा , विराट कोहली,श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान),केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़।

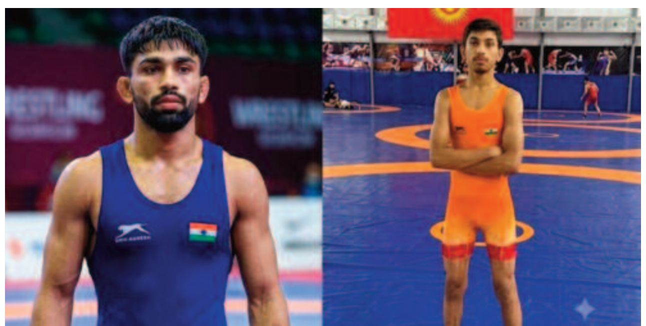

नीरज पटेल ने जीता कांस्य पदक

थाईलैंड में एशियन कुश्ती में जापान के नारू सेंबा को हराया

खंडवा,03 जुलाई 2026। जिले के गांव बोरगांव खुर्द के 18 वर्षीय कुश्ती खिलाड़ी नीरज पिता विट्ठल पटेल ने बुधवार को थाईलैंड में एशियन कुश्ती में जापान के नारू सेंबा को 4-3 से हराकर भारत के लिए कांस्य पदक जीता। नीरज ने अंडर-20 एशियन चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग में प्रदर्शन करते हुए यह पदक हासिल किया। विदित हो कि खंडवा जिला प्रदेश में कुश्ती का हब बन चुका है। वहीं बोरगांव खुर्द कुश्ती की खान बन चुका है। बोरगांव खुर्द की माधुरी और छाया पटेल ने कुश्ती के क्षेत्र में उज्जैन में प्रथम स्थान पाया और शीघ्र ही में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए हरियाणा के रोहतक में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेंगी।

महिला टी 20 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड,दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराया

मुंबई,03 जुलाई 2026। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां मेजबान इंग्लैंड की महिला टीम ने अपनी ऐतिहासिक सरजमीं पर शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। प्रतिष्ठित 'द ओवल' मैदान पर खेले गए टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रनों से शिकस्त देकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम ने कप्तान नेट शीवर-ब्रंट और पूर्व कप्तान हीदर नाइट की बेहतरीन अर्धशतकीय पारियों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 169 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में रनों के दबाव के आगे दक्षिण अफ्रीकी टीम बिखर गई और 20 ओवर में 8 विकेट खोकर महज 129 रन ही बना सकी। अब खिताबी जंग में इंग्लैंड का सामना 5 जुलाई (रविवार) को छह बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम से होगा।

शुरुआती झटकों के बाद इंग्लैंड की रिकॉर्डतोड़ वापसी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद निराशाजनक और झटकेदार रही। टीम ने महज 35 रनों के कुल स्कोर पर अपने तीन शीर्ष और इन-फॉर्म बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे। सलामी बल्लेबाज एमी जोन्स, डैनी व्याट-हॉज और एलिस कैप्सी अफ्रीकी गेंदबाजों की सटीक लाइन-लेंथ के आगे सस्ते में पवेलियन लौट गईं। दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी तेज गेंदबाज शबनिम इस्माइल और मारिजन काप ने नई गेंद से धारदार गेंदबाजी करते हुए शुरुआती ओवरों में इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया था।

CMYK

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खरीफ-2026 एवं संभावित अल्प वर्षा की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की

अल्प वर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार : सीएम साय

खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता,जल संरक्षण,वैज्ञानिक खेती और ग्रामीण रोजगार पर विशेष जोर...

वीबी-जी राम जी योजना के माध्यम से जल सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती

छत्तीसगढ़ को 46 हजार टन से अधिक डीएपी की आपूर्ति प्राप्त

रायपुर,03 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने निवास कार्यालय में खरीफ सीजन-2026 के दौरान संभावित अल्प वर्षा की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग तथा विकसित भारत-बीवी-जी राम जी योजना की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में मौसम की संभावित स्थिति, खाद एवं बीज की उपलब्धता, जल संरक्षण, सिंचाई प्रबंधन,वैज्ञानिक खेती तथा ग्रामीण रोजगार से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और किसी भी परिस्थिति में उन्हें खाद,बीज, तकनीकी मार्गदर्शन अथवा आवश्यक संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करते हुए प्रत्येक जिले के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार रखें। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त डीएपी उर्वरक उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। इसके सकारात्मक परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ को 46 हजार टन से अधिक डीएपी की आपूर्ति प्राप्त हुई है, जो सामान्य से अधिक है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध होगा तथा खरीफ सीजन की तैयारियों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान की फसल के लिए आवश्यक सिंचाई जल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में जल स्त्रोतों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कृषि विभाग को निर्देशित किया कि किसानों को कम एवं मध्यम अवधि में पकने वाली धान की किस्मों, डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर), कतार पद्धति से बुवाई,बीज उपचार,नमी संरक्षण तथा वैज्ञानिक खेती की आधुनिक तकनीकों के प्रति व्यापक रूप से जागरूक किया जाए। साथ ही उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में दलहन एवं तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, जिससे किसानों को बेहतर आय के अवसर प्राप्त हों और कृषि जोखिम कम हो। मुख्यमंत्री साय ने किसानों से अपील की कि वे कृषि संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या अथवा तकनीकी सलाह के लिए कृषि महाविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों,अनुसंधान संस्थानों तथा कृषि विभाग के विशेषज्ञों से संपर्क करें और वैज्ञानिक खेती को अपनाएं। उन्होंने अमानक बीज एवं उर्वरकों की बिक्री तथा कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में बताया गया कि राज्य में खाद एवं बीज का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है तथा सभी जिलों में समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। बैठक में बताया गया कि अर्ली वेरायटी के धान बीज बीज निगम के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराने की संपूर्ण तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संभावित अल्प वर्षा जैसी परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जल संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बनाया जाएगा। उन्होंने 'मोर गांव मोर पानी' अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए वर्षा जल संरक्षण, खेत तालाब, जल संरचनाओं के निर्माण तथा भूजल संवर्धन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आकाशीय बिजली जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की सुरक्षा के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विकसित 'सचेत', 'दामिनी' और 'मेघदूत' मोबाइल एप का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि समय पर मौसम संबंधी जानकारी किसानों तक पहुंच सके। साथ ही सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उचित दर पर खरपतवारनाशक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे उत्पादन लागत कम हो और फसल सुरक्षित रह सके।

वीबी-जी राम जी योजना बनेगी जल सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि का मजबूत आधार : बैठक में बताया गया कि 1 जुलाई 2026 से योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मजदूरी दर 300 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, जल सुरक्षा,जल संरचनाओं के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निर्देश दिए कि वीबी-जी राम जी योजना के माध्यम से ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाए,जिनसे एक ओर ग्रामीणों को निरंतर रोजगार प्राप्त हो और दूसरी ओर प्रदेश की जल सुरक्षा मजबूत हो। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में किया गया प्रत्येक प्रयास आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का आधार बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और ग्रामीण परिवारों के हितों की रक्षा,कृषि उत्पादन को सुरक्षित रखने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृषि विश्वविद्यालय द्वारा नियमित रूप से जारी किए जाने वाले बुलेटिनों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक प्रभावी जनजागरूकता अभियान तैयार किया जाए,ताकि यह जानकारी किसानों तक जमीनी स्तर पर पहुँचे। साथ ही सोशल मीडिया एवं पारंपरिक मीडिया के माध्यम से भी इनका व्यापक प्रसार सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह,कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल परदेशी,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी,कृषि संचालक राहुल देव,विकसित भारत वीबी-जीरामजी योजना के आयुक्त तारणप्रकाश सिन्हा,भारत मौसम विज्ञान विभाग की विशेषज्ञ श्रीमती गायत्री वानी,इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान सेवाओं के निदेशक विवेक कुमार त्रिपाठी सहित कृषि, मौसम एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कार के गुप्त चैंबर से 62 किलो गांजा बरामद,36.13 लाख की संपत्ति जब्त

महासमुंद,03 जुलाई 2026। महासमुंद पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भवानीपटना (ओडिशा) से इंदौर (मध्यप्रदेश) ले जाए जा रहे 62.160 किलोग्राम गांजा की खेप जब्त की है। पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गांजा,तस्करी में प्रयुक्त कार और मोबाइल फोन सहित कुल 36 लाख 13 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की है। आरोपियों के खिलाफ कोमाखान थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसार,जिले की सीमा पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और थाना पुलिस लगातार जांच अभियान चला रही है। इसी दौरान कोमाखान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा से एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार (एमपी-13-जेडडब्ल्यू-9964) में दो व्यक्ति बड़ी मात्रा में गांजा लेकर छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्यप्रदेश जा रहे हैं। सूचना के आधार पर ग्राम गोयनाबाहरा के पास वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई। जांच में पता चला कि तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए कार में दो गुप्त चैंबर बनवाए थे,जिनमें गांजा छिपाकर रखा गया था। तलाशी के दौरान कुल 62.160 किलोग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 31 लाख 8 हजार रुपये है, बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार

आरोपियों ने अपनी पहचान सुरेश मालवीय (30 वर्ष) निवासी देवली पीपलोन,थाना आगर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) तथा एल्कार सेन (30 वर्ष) निवासी मारूबल्डिया,थाना बड़ोद,जिला आगर (मध्यप्रदेश) के रूप में बताई। दोनों ने स्वीकार किया कि वे गांजा ओडिशा के भवानीपटना से खरीदकर इंदौर ले जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 62.160 किलोग्राम गांजा, पांच लाख रुपये कीमत की कार और पांच हजार रुपये कीमत का एक मोबाइल फोन जब्त किया है। जब्त संपत्ति का कुल मूल्य 36 लाख 13 हजार रुपये आंका गया है। कोमाखान थाना में आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 99/2026 के तहत धारा 20,29 एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों और वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही है।

आधार कार्ड में नाम सुधरवाना हुआ मुश्किल

गजट नोटिफिकेशन अनिवार्य होने से बढ़ी परेशानी...

रायपुर,03 जुलाई 2026। आधार कार्ड में अपने नाम या सरनेम में सुधार करवाना अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। केंद्र सरकार ने नाम परिवर्तन के नियमों को सख्त कर दिया है। छोटी सी त्रुटि या नाम में बदलाव के लिए अब सरकारी गजट (राजपत्र) में अधिसूचना जारी करवाना जरूरी हो गया है। इस नई व्यवस्था के कारण आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी तौर पर इस पूरी प्रक्रिया का शुल्क 1100 रुपए से शुरू होता है। लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गई है कि आम आदमी बिना किसी वकील की सहायता के इसे आसानी से पूरा नहीं कर सकता। आवेदन तैयार करने,शपथ-पत्र बनवाने और सार्वजनिक सूचना जारी करने जैसे कामों के लिए वकील लोगों से 10 हजार से लेकर 20 हजार रुपए तक की मांग कर रहे हैं। इतनी बड़ी रकम चुकाने के बाद भी लोगों का काम तुरंत नहीं हो रहा है। इस पूरी कागजी प्रक्रिया में कम से कम छह महीने का समय लग रहा है। इसके साथ ही एक बड़ी मुश्किल यह भी है कि राजपत्र में प्रकाशन का मुख्यालय राजनांदगांव में स्थित

है, जिससे रायपुर और आसपास के लोगों की भागदौड़ और ज्यादा बढ़ गई है।

किन स्थितियों में राजपत्र में प्रकाशन अनिवार्य है?

- **मेजर नाम चेंज :** यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा नाम बदलना चाहता है, या शादी के बाद केवल सरनेम बदलने के बजाय पूरा नाम ही नया रखना चाहता है, तो गैजेट नोटिफिकेशन देना होगा।
- **लिमिट खत्म होने पर :** नियम के अनुसार एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में केवल दो बार ही आधार में नाम सुधार करवा सकता है। यह लिमिट पार होने पर इसे अपवाद माना जाता है। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन और क्षेत्रीय कार्यालय की अनुमति मांगी जाती है।
- **उपनाम (सरनेम) पूरी तरह बदलना :** बिना किसी कानूनी आधार (जैसे शादी) के अपना सरनेम पूरी तरह बदलने पर राजपत्र में प्रकाशन मांगा जाता है।
- **धर्म परिवर्तन या कानूनी कारण :** धर्म बदलने या कोर्ट के आदेश पर नाम बदलने की स्थिति में भी यह नियम लागू होता है।

परेशान लोगों के उदाहरण...

स्पेलिंग सुधार के लिए 12 हजार फीस : रजबंधा मैदान,एकात्म परिसर के पास रहने वाले मोहसिन खान को अपने बच्चे के आधार में केवल स्पेलिंग ठीक करवानी थी। आधार सेंटर जाने पर उन्हें वकील से संपर्क करने को कहा गया। वकील ने बताया कि राजपत्र में अधिसूचना के बाद ही सुधार होगा और इसके लिए 12 हजार रुपए फीस और छह महीने का समय लगेगा।

सरनेम बदलने के लिए 18 हजार की मांग : संजय नगर की रहने वाली शांति देवी ने तलाक के बाद दूसरी शादी की है। वे अपनी पहली शादी से हुए बच्चे का नाम और सरनेम बदलवाना चाहती थीं। सेंटर ने उनसे राजपत्र की कॉपी मांगी।

निर्धारित सरकारी शुल्क एक नजर में...इस पूरी प्रक्रिया पर ई-डिस्ट्रिक्ट रायपुर की मैनेजर कीर्ति शर्मा का कहना है कि विशेष परिस्थितियों में या दस्तावेजों की कमी होने पर नाम बदलवाने के लिए राजपत्र में प्रकाशन अनिवार्य किया गया है। यह केंद्र सरकार का नियम है।

बस्तर में नक्सलियों की 'यूनिवर्सिटी' बंद
21 साल बाद पीडिया क्षेत्र में खुले 11 स्कूल
500 से अधिक बच्चे अब गढ़ेंगे अपना भविष्य

बीजापुर,03 जुलाई 2026। कभी नक्सलियों की 'यूनिवर्सिटी' कहे जाने वाले पीडिया क्षेत्र में अब स्कूल की घंटियां गूंज रही हैं। 21 साल बाद सलवा जुडूम के दौरान बंद हुए 11 स्कूलों को फिर से शुरू किया गया है। कलेक्टर विश्वदीप की पहल पर 3 पंचायतों के 539 बच्चों को अपने गांव में ही पढ़ाई का मौका मिला है। यह भय से विश्वास और अंधकार से ज्ञान की ओर बढ़ते बस्तर की नई तस्वीर है। पीडिया और आसपास का इलाका नक्सलियों की भर्ती और ट्रेनिंग का गढ़ था। यहां वे अपने स्कूल और आश्रम भी चलाते थे। माओवादी हिंसा के कारण 21 साल पहले यहां के स्कूल बंद हो गए और भवन ध्वस्त कर दिए गए। अब नक्सलवाद कमजोर होने के बाद पीडिया,पेदापाल,छोटेगोटोडी,कुएम,मदपाल,अंडरी,इडेनार, डोंडीतुमनार,मिरगानघोटूल,गमपुर और तमोड़ी गांव में स्कूल फिर शुरू हुए हैं। यहां के बच्चों को अब दूर नहीं जाना पड़ेगा।

17 जजों का ट्रांसफर,छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

बिलासपुर,03 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग के 17 न्यायिक अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश के तहत कई जिला-सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला-सत्र न्यायाधीश और हाईकोर्ट में पदस्थ अधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई हैं। जारी आदेश के अनुसार, जगदलपुर के प्रथम जिला-सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत को स्पेशल जज, जगदलपुर नियुक्त किया गया है। वहीं, हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के सचिव ओमप्रकाश जायसवाल को हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा बलौदाबाजार के प्रधान जिला-सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी को हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (विजिलेंस) बनाया गया है। वहीं, बलौदाबाजार के प्रथम जिला-सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा का तबादला छत्तीसगढ़ न्यायिक अकादमी, बिलासपुर में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर किया गया है।

शिक्षा मंत्री के गृह जिले में बड़ा आंदोलन : संविलियन की मांग पर अड़े 1532 अतिथि शिक्षक, अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

दुर्ग,03 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रांतीय अतिथि शिक्षक विद्यामितान कल्याण संघ के नेतृत्व में प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी सरकारी सेवा में विलय यानी संविलियन की मांग को लेकर इन शिक्षकों ने पूरी तरह से काम बंद कर दिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के खुद के गृह जिले दुर्ग समेत राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इस कलमबंद हड़ताल के कारण सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का काम पूरी तरह से ठप होने की आशंका

बढ़ गई है। आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वे बस्तर के बेहद पिछड़े और दूरदराज के इलाकों सहित राज्य के विभिन्न जिलों के स्कूलों में पिछले 12 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही स्कूलों में होने वाले अन्य सभी सरकारी और विभागीय कामों में भी उनकी पूरी ड्यूटी लगाई जाती है। इतनी कड़ी मेहनत और लंबे अनुभव के बावजूद उन्हें हर महीने मेहनताने के रूप में सिर्फ 20000 रुपये ही दिए जाते हैं। उनकी साफ मांग है कि उन्हें भी नियमित यानी सरकारी शिक्षकों की तरह विभाग में शामिल किया जाए और समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। शिक्षकों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में इस समय लगभग 1532 विद्यामितान अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इतने सालों से लगातार काम करने के बाद भी उन्हें न तो कोई सरकारी छुट्टी मिलती है और न ही किसी अन्य तरह की जरूरी सुविधा दी जा रही है।

आंदोलन को मिला विपक्ष का साथ,सरकार को घेरा

शिक्षकों के इस बड़े आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। दुर्ग के कांग्रेस जिला अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल खुद धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने शिक्षकों की मांगों को अपना पूरा समर्थन दिया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने इन विद्यामितान शिक्षकों की समस्या को समझते हुए उनका मानदेय बढ़ाकर 20000 रुपये किया था। अब ये शिक्षक नियमितीकरण की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन खुद शिक्षा मंत्री के जिले में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी सिर्फ उन्हें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर कटवा रहे हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम भी इस पूरे प्रदर्शन पर नजर रखे हुए है।

अपनी इन्हीं दिक्कतों को लेकर वे पहले भी स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी शासन या विभाग की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नाराज शिक्षकों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक उनका यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा।

तमनार हिंसा का मास्टरमाइंड राजेश मरकाम गिरफ्तार,भीड़ को उकसाने और महिला टीआई की पिटाई के मामले में थी पुलिस को तलाश

रायगढ़,03 जुलाई 2026। रायगढ़ जिले के तमनार में दिसंबर 2025 में हुई हिंसक घटनाओं का मास्टरमाइंड राजेश मरकाम (39) को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। कसडोल निवासी राजेश मरकाम पर भीड़ को उकसाने,पुलिस पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचाने का गंभीर आरोप है। पुलिस को मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर तमनार और पूंजीपथरा पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर उसे ग्राम बरपाली से हिरासत में लिया। दिसंबर 2025 में धौराभाठा में आयोजित जनसुनवाई के विरोध से जुड़ा है। जेपीएल कोयला खदान सेक्टर-1 कोल ब्लॉक से प्रभावित 14 गांवों के ग्रामीण 12 दिसंबर से धरने पर थे। 27 दिसंबर की सुबह स्थिति तब बेकाबू हो गई जब लिबरा चौक पर

करीब 1000 की भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने न केवल यातायात बाधित किया, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल की शांति बनाए रखने की अपील को भी दरकिनार कर दिया। दोपहर के समय भीड़ ने हिंसक रुख अपना लिया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिस टीम पर पत्थर व डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान तमनार थाना प्रभारी कमला पुषाम समेत कई पुलिसकर्मी और महिला आरक्षक घायल हो गए। इसके बाद उग्र भीड़ ने मौके पर खड़ी पुलिस बस, जीप और एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया।

ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का पहली बार संचालन

रायपुर,03 जुलाई 2026। यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल द्वारा ट्रेन संख्या 08411 ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस स्पेशल का पहली बार संचालन किया जा रहा है। यह विशेष ट्रेन ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं गुजरात के यात्रियों को सीधी एवं सुविधाजनक रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। अमृत भारत एक्सप्रेस आधुनिक एलएचबी कोचों से सुसज्जित है। गाड़ी संख्या 19022/19021 ब्रह्मपुर-उधना-ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस जो हफ़्ते में 03 दिन चलेगी की पहली बार यात्रा विजयनगरम-टिटलागढ़ -रायपुर -दुर्ग के रास्ते दिनांक 06.07.2026 को नीचे दी समय सारणी के अनुसार चलेगी। यह ब्रह्मपुर से उधना के लिए एक स्पेशल ट्रेन होगी।

विवादित अफसर मक्सी कुजूर को स्थायी प्रमुख अभियंता बनाने पद खाली

रायपुर,03 जुलाई 2026। 30 जून 2026 को जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता शंकर ठाकुर सेवा निवृत्त हो गए हैं, लेकिन तीन दिन बीत जाने के बाद भी विभाग नए प्रमुख अभियंता की नियुक्ति को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाया है। विभाग में शीर्ष पद खाली रहने से निर्णय लेने की क्षमता और प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, शासन-प्रशासन के कुछ आला अधिकारियों द्वारा विभाग की कमान अपने नियंत्रण में रखते हुए मक्सी कुजूर को स्थायी प्रमुख अभियंता बनाने के लिए अंदरखाने प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी कवायद के चलते प्रमुख अभियंता का पद जानबूझकर खाली रखा गया है, जबकि विभाग में पहले से ही कई वरिष्ठ मुख्य अभियंता पदस्थ हैं जो

इस पद के लिए दावेदार हैं। मक्सी कुजूर पहले से ही विवादों में घिरे अधिकारी रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वे रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों पकड़े गए थे और उस समय उच्च न्यायालय बिलासपुर से उन्हें अंतरिम राहत मिल गई थी। किंतु वर्तमान में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्रमांक 38024/2026 दायर होने की जानकारी सामने आई है, जिससे उनकी तैनाती को लेकर और भी गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। प्रमुख अभियंता जैसे अहम पद पर स्थायी नियुक्ति न होने से विभागीय कार्यों और राज्य के सिंचाई-जल संसाधन परियोजनाओं,वर्षा ऋतु, विधानसभा सत्र पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों और आरोपों से जुड़े तथ्यों का स्पष्ट निराकरण नहीं हो जाता, तब तक विवादित अधिकारी को विभाग की कमान सौंपना शासन-प्रशासन की विश्वसनीयता पर सीधे प्रश्नचिह्न लगाता है। स्थिति यह है कि मक्सी कुजूर को फिलहाल दो मुख्य अभियंता कार्यालयों का प्रभार दे दिया गया है–एक मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना रायपुर और दूसरा अतिरिक्त प्रभार मुख्य अभियंता, महानदी-गोदावरी कछार, रायपुर। वहीं इसी कार्यालय में पदस्थ मुख्य अभियंता सेलवेस्टर मिंज को प्रमोशन के बाद भी कोई स्वतंत्र पदस्थापना नहीं दी गई है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह*(पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)